विक्रम संवत् 2082 ▪ पौष/माघ मास (11) ▪ 01 जनवरी 2026 ▪ मूल्य : 23 रु.

चरैवेति

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

"वंदे मातरम्"

आर.एन.आई. पंजीयन क्र.017261/69, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/297/2024-26, पृष्ठ संख्या-44, प्रकाशन दिनांक प्रत्येक माह की 10 तारीख, पोस्टिंग प्रत्येक माह की 15 एवं 20 तारीख

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "सदैव अटल स्मारक" पर पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101 वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

▪ भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी ने कार्यभार ग्रहण किया।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ओमान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित किया।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

▪ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की।

अनुक्रमणिका

» **संपादकीय** - संजय गोविन्द खोचे 04

- "वंदेमातरम्" को आत्मसात करना है

» **कवर स्टोरी** - "वंदे मातरम्" 05

- "वंदेमातरम्" ने भारतवर्ष के विचार को पुनर्जीवित किया - पीएम मोदी

- "वंदे मातरम्" 09

» "वंदे मातरम्" राष्ट्र पुनर्निर्माण का आधार - अमित शाह

- भाजपा सरकार के दो साल 12

» प्रदेश में अकल्पनीय विकास-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

» प्रदेश में विकास नई ऊंचाइयों पर-हेमंत खंडेलवाल

- मतदाता शुद्धिकरण 15

» शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है - अमित शाह

- अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट 19

» मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनेगा- अमित शाह

» निवेश, रोजगार और समावेशी विकास का नया मॉडल मध्य प्रदेश...

- Transforming Tomorrow 22

» अब, भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर - पीएम मोदी

- कविता : अटल बिहारी वाजपेयी 24

» गीत नहीं गाता हूँ

- पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज 25

» गांव-गांव पहुंच रहा है इलाज-जगत प्रकाश नड्डा

» परियोजनाओं व विकास कार्यों की मिलेगी सौगात-डॉ. मोहन यादव

- लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा 27

» डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जारी रहेगा- अमित शाह

- वीर बाल दिवस 30

» शहादत ने संघर्ष, त्याग और बलिदान दिखाया - डॉ. मोहन यादव

- कृषक सम्मेलन 31

» प्राकृतिक खेती से किसानों की समृद्धि - अमित शाह

- राष्ट्र प्रेरणा स्थल 32

» राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र -निर्माण के लिए समर्पित - पीएम मोदी

- अटल स्मृति वर्ष 34

» विचार जो अटल थे, संकल्प जो मोदी जी ने साकार...

» हमारे अटलजी-राष्ट्र सेवा और सुशासन के युगपुरुष

- मन की बात 36

» 'विकसित भारत' का संकल्प पूरा होगा

- अटल जी 39

» अटल जी का योगदान अद्वितीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

- त्यौहार 40

» सूर्य नारायण का पर्व है मकर संक्रान्ति

- विचार प्रवाह 41

» संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है

• मुख्य व्रत-त्यौहार

1. प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत 2. व्रत पूर्णिमा 3. स्नान दान, पौषी पूर्णिमा, षोडषकारण व्रत प्रा. 6. अं. सं. गणेश, तिल चौथ व्रत 14. षट्तिला ग्यारस, मकर संक्रांति 15. संक्रांति स्नान, तिल द्वादशी 16. प्रदोष व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत 17. ऋषभदेव निर्वाणोत्सव 18. स्ना. दा. श्रा., मौनी अमावस 20. चन्द्रदर्शन 22. तिल कुंद, विनायकी चतुर्थी 23. बसंत पंचमी 24. शीतला षष्ठी 25. अचला, रथ सप्तमी 26. भीष्माष्टमी 27. महानंदा नवमी 29. जया/अजा, भीष्म ग्यारस 30. तिल / भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत, रत्नत्रय व्रत प्रारम्भ

• मुख्य जयंती-दिवस

3. छेरछेरा, मोती माता मंदिर 12. महर्षि महेश योगी जयंती 20. अ. भा. मारवाड़ी युवा मंच स्था. दि. 23. माँ परमेश्वरी जयंती, म. खटवांग, कवि निराला जयंती, सुभाषचंद्र बोस ज., रा. पराक्रम दि. 24. भ. देवनारायण जयंती 25. महर्षि नवल जयंती 28. लाला लाजपतराय जयंती 31. रामचरण प्रभु, वीर तेजाजी एवं प्रभु नित्यानंद जयंती

वर्ष-57, अंक : 11, भोपाल, जनवरी 2026

हमारे प्रेरणास्रोत

पं. दीनदयाल उपाध्याय

ध्येय बोध

हमने धर्म के आधार पर लोक पालन और राज्य की व्यवस्था का विधान किया। केवल सत्ता भोग के लिए राज स्थापना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं। धर्म के लिए राज्य की आवश्यकता हुई इसलिए धर्म से प्रेरणा जरूरी है। राजा धर्म रक्षण के लिए उत्तरदायी है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

•

सम्पादक

मुद्रक एवं प्रकाशक

संजय गोविंद खोचे*

•

सहायक सम्पादक

पं. सलिल मालवीय

•

व्यवस्थापक

योगेन्द्रनाथ बरतरिया

•

पं. दीनदयाल विचार प्रकाशन म.प्र. के लिये मुद्रक एवं प्रकाशक संजय गोविंद खोचे द्वारा पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 से प्रकाशित

एवं एम. पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेस-II, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा - 201 305 से मुद्रित.

•

संपादकीय पता

पं. दीनदयाल परिसर,
ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016
e-mail:charevetibpl@gmail.com
web site:www.charaiveti.org

मूल्य- तेईस रुपये

*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार

''वंदेमातरम्'' को आत्मसात करना है

जननी और जन्मभूमि की रक्षा के लिए हंसते- हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ''वंदेमातरम्'' वह ऊर्जा का केन्द्र था, ध्येय वाक्य था जिसकी प्रेरणा से भारतवंशियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने में भी तनिक हिचक भी नहीं की।

''अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥''

प्रभु श्री रामचन्द्र जी, जो अनन्त हैं, हरि हैं, विश्वमय हैं, वेद जिनकी अपनी वाणी है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि- **लंका विजय के बाद भी सोने की लंका में कुछ भी रूचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान हैं।**

श्री राम जी के आदर्श भारतवंशियों के लिए मार्गदर्शक हैं, पथ प्रर्दशक हैं, हमारी प्राणवायु हैं। जननी और जन्मभूमि की रक्षा के लिए हंसते-हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ''वंदेमातरम्'' वह ऊर्जा का केन्द्र था, ध्येय वाक्य था जिसकी प्रेरणा से भारतवंशियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने में भी तनिक हिचक भी नहीं की। वक्त बदला, जन्मभूमि के लिए बलिदान रंग लाया, भारत गुलामी से मुक्त हुआ।

''वंदेमातरम्'' स्वतंत्रता आंदोलन में वीरों के लिए जीवन का ध्येय था, पर विडम्बना ही रही कि ''वंदेमातरम्'' भी वोट बैंक की राजनीति के चलते विवादित कर दिया गया।

''वंदेमातरम्'' से मिली ऊर्जा के ही परिणाम स्वरूप भारत का एकीकरण सम्भव हो पाया था, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं। भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथों में आई। भारत में कानून का शासन आया। वास्तव में आज का भारत उन सभी वीरों का ऋणी है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में सर्वोच्च बलिदान ही नहीं, जरा सा भी योगदान दिया है। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात् बीच के कालखण्ड में वोट बैंक की राजनीति शासन व्यवस्था पर हावी हो गई। जिसने ना तो स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं का ही आदर रखा, न सर्वोच्च बलिदान की भावना का सम्मान किया न ही स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का सम्मान किया।

''वंदेमातरम्'' राजनीति के लिए चर्चा का विषय ही नहीं है, यह तो वह पुण्य स्मरण है जिसने हर भारतीय को भारतीय होने का गौरव प्रदान किया है।

''वंदेमातरम्'' ही वह भाव है जिससे प्राप्त ऊर्जा ही भारत को दसवीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाती है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाती है। धारा 370 की दीवाल को हमेशा-हमेशा के लिए ढहा देती है, एक देश- एक कर के सपने को साकार करती है। तीन तलाक की तलवार ही तोड़ देती है। हर घर जल, हर गरीब को इलाज निःशुल्क, विश्वस्तरीय अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से अनाज की व्यवस्था, धुएं के चूल्हे से माता बहनों को मुक्ति, हर परिवार के लिए स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था, आयातक देश का निर्यातक देश में परिवर्तन, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र, सक्षम व समर्थ देश, केन्द्र शासन से लेकर ग्राम पंचायत की व्यवस्था तक महिलाओं की भागीदारी की सुरक्षा, गरीब किसानों को सम्मान निधि जैसे तमाम परिवर्तनों के पीछे केवल ''वंदेमातरम्'' का भाव ही है। माँ भारती की सेवा ही ''वंदेमातरम्'' है। कानून का राज ही ''वंदेमातरम्'' है। सुरक्षित, समृद्ध व संगठित भारत ही ''वंदेमातरम्'' है। विकसित भारत @ 2047 ही ''वंदेमातरम्'' का लक्ष्य है। देश का सौभाग्य है कि ''वंदेमातरम्'' की 150 वर्ष की यात्रा के पड़ाव पर देश का नेतृत्व श्री नरेन्द्र मोदी जैसे योग्य व सक्षम हाथों में है, जिससे देश ''वंदेमातरम्'' की दिशा में तेजी से आगे अग्रसर है।

देश की प्रगति उन असंख्य सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजली है जिनके बलिदान के पीछे उन्नत, सक्षम व समृद्ध भारत का सपना था, जिसे आज का भारत बिना रूके, बिना थके, पूरी तन्मयता के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

''वंदेमातरम्'' की भावना के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था देश के नागरिकों के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। विदेशियों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। चुनाव आयोग को भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का जिम्मा सोंपा गया है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि कोई भी योग्य मतदाता चुनाव में वोट डालने से रह न जावे और कोई भी अयोग्य मतदाता वोट न डाल पाये। अगर विदेशी व्यक्ति भारत के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची शुद्धिकरण के कार्य को पूरी स्पष्टता व जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है। राजनैतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ कर देश हित में, लोकतंत्र के हित में, देश के भविष्य के लिए मतदाता सूची शुद्धिकरण के पुनीत कार्य में चुनाव आयोग का सहयोग व सर्मथन करना चाहिए।

इथियोपिया ने भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया। यह सम्मान देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है जिन्होंने भारत इथियोपिया मैत्री को मजबूत किया है, बल दिया है।

मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जी के नेतृत्व में गठित सरकार को दो वर्ष पूर्ण हो गये हैं। इन दो वर्षों के कार्यकाल में मध्यप्रदेश ने एतिहासिक प्रगति की है। सरकार के नवाचारों से मध्यप्रदेश समृद्ध हो रहा है, नये उद्योग-धन्धों की श्रृंखला स्थापित होने जा रही है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, प्रदेश अब उस स्थिती में आ रहा है कि प्रदेश दूसरे राज्यों के युवाओं को भी अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिती में भी सुधार आवेगा। विकसित भारत@2047 में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री जी व भाजपा संगठन के प्रयासों से प्रदेश में नये युग का प्रारम्भ होगा।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे कर भाजपा सरकार ने छोटे किसानों की राह को आसान बनाया है, पानी की भी बचत होगी और आम जनता को विभिन्न प्रकार के रोगों से निजात मिलेगी, भाजपा सरकार का यह प्रयास सराहनीय है।

युगदृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष प्रेरणा दिलाता है कि राजनीति में संवाद व सहमति बनी रहना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोच्च है, भाषा की मर्यादा व व्यवहार में विनम्रता भारत की पहचान है। गुलामी के कालखण्ड को पीछे छोड़ कर नये भारत का निर्माण निरंतर जारी रहना चाहिए। ▪

(संजय गोविन्द खोचे)
सम्पादक

''वंदेमातरम्'' ने भारतवर्ष के विचार को पुनर्जीवित किया - पीएम मोदी

जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस ''वंदे मातरम्'' का पुण्य स्मरण करना, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि ''वंदे मातरम्'' के 150 वर्ष निमित्त, इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड, जो हमारे सामने इतिहास के अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। आने वाली पीढ़ियां के लिए भी, यह शिक्षा का कारण बन सकती है।

यह एक ऐसा कालखंड है, जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। हमने संविधान के 75 वर्ष गौरव पूर्व मनाए हैं। देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती मना रहा है और गुरु तेग बहादुर जी का 350 वां बलिदान दिवस मनाया है और हम ''वंदे मातरम्'' की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। ''वंदे मातरम्'' 150 वर्ष की यह यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है।

''वंदे मातरम्'' को जब 50 वर्ष हुए, तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और ''वंदे मातरम्'' के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब ''वंदे मातरम्'' 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब ''वंदे मातरम्'' 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने-मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस ''वंदे मातरम्'' के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए, तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया।

150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही ''वंदे मातरम्'' है, जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक नेतृत्व इस ''वंदे मातरम्'' के जयघोष में था।

''वंदे मातरम्'' 150 निमित्त चर्चा के लिए

कोई पक्ष-प्रतिपक्ष नहीं है, एक्चुअली ऋण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस ''वंदे मातरम्'' के कारण लक्ष्यावादी लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं और इसलिए हम सभी के लिए''वंदे मातरम्'' के ऋण स्वीकार करने का यह पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के ''वंदे मातरम्'' की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा देश एक स्वर से ''वंदे मातरम्'' बोलकर आगे बढ़ा, फिर से एक बार अवसर है कि आओ, हम सब मिलकर चलें, देश को साथ लेकर चलें, आजादी का दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए ''वंदे मातरम्'' 150 सब की प्रेरणा बने, सब की ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बनाकर के रहें, इस संकल्प को दोहराने के लिए ''वंदे मातरम्'' बहुत बड़ा अवसर है।

''वंदे मातरम्'' की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति-भांति के दबाव डाल रही थी, भांति-भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, God Save The Queen, इसको भारत में घर-घर पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से ''वंदे मातरम्'' का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद, 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उस गीत का उसमें समावेश किया गया।

''वंदे मातरम्'' ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था, जो हजारों वर्षों से भारत की रग-रग में रचा-बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ, ''वंदे मातरम्'' के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। ''वंदे मातरम्'' यह सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, सिर्फ अंग्रेज जाएं और हम खड़े हो जाएं, अपनी राह पर चलें, इतनी मात्र तक ''वंदे मातरम्'' प्रेरित नहीं करता था, वो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था और ''वंदे मातरम्'' की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार-बार हमारे सामने आई है। जब ''वंदे मातरम्'' कहते हैं, तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है ''माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'' अर्थात् यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं।

यही वह विचार है, जिसको प्रभु श्री राम ने भी

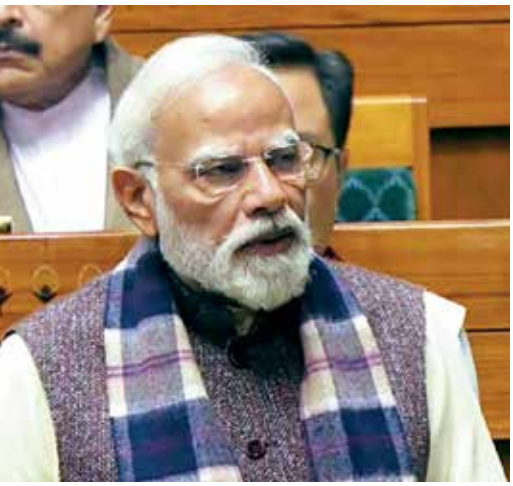

लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था

''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी''।

''वंदे मातरम्'', यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है।

बंकिम दा ने जब ''वंदे मातरम्'' की रचना की, तो स्वाभाविक ही वह स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ''वंदे मातरम्'' हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए ''वंदे मातरम्'' की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, ये शब्द हैं ''वंदे मातरम्''

है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आव्हान है, यह शब्द ''वंदे मातरम्'' है।

उष्ण शोणित से लिखो, वक्तस्थलि को चीरकर वीर का अभिमान है, यह शब्द ''वंदे मातरम्'' है।

जब ''वंदे मातरम्''150 का आरंभ हो रहा था, तो मैंने कहा था, ''वंदे मातरम्'' हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी। उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी, भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सकें, ऐसी एक फैशन बन गई थी और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे, वह लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरनें के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए, ''वंदे मातरम्'' के भारत के सामर्थ्यशाली रूप को प्रकट करते हुए लिखा थाः-

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी।
नमामि त्वां नमामि कमलाम्,
अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्॥
वंदे मातरम्॥

अर्थात् भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी हैं और दुश्मनों के सामने अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी हैं।

यह शब्द, यह भाव, यह प्रेरणा, गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया की लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है, यह गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थीं, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें है।

''वंदे मातरम्'' इसका जो जन-जन से जुड़ाव था, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है।

जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन-जीवन की यात्रा का प्रवाह, उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा ''वंदे मातरम्'' की भावनाओं से गुजरता था। उसके तट पर पल्लवित होता था, ऐसा भाव, काव्य शायद दुनिया में कभी उपलब्ध नहीं होगा।

अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था और जिस प्रकार से वह अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि, जब तक भारत को बाटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकडों में नहीं बाटेंगे, भारत में ही लोगों को एक-दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है और अंग्रेजों ने बाटों और राज करो, इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे, वह एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का यह जो सामर्थ्य है, वह पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया, तो यह देश भी टूट जाएगा और वो यावच चन्द्र-दिवाकरौ राज करते रहेंगे, यह उनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में यह पाप किया, तो ''वंदे मातरम्'' चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए ''वंदे मातरम्''गली-गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीज और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन ''वंदे मातरम्'' एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया।

बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब ''वंदे मातरम्'' हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला, बंकिम दा का यह भाव सूत्र, बंकिम बाबू ने यह जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा, उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी, अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, ''वंदे मातरम्'' शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने नेतृत्व किया, लक्ष्यावधि महिलाओं ने योगदान दिया। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बारीसाल में ''वंदे मातरम्'' गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो बारीसाल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है और उस समय बारीसाल के हमारे माताएं, बहने, बच्चे मैदान में उतरे थे, ''वंदे मातरम्'' के स्वाभिमान के लिए, इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी और तब बारीसाल कि यह वीरांगना श्रीमती सरोजिनी घोष, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावनाओं को देखिए और उन्होंने कहा था की ''वंदे मातरम्'' यह जो प्रतिबंध लगा है, जब तक यह प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां जो पहनती हूं, वो निकाल दूंगी। भारत में वह एक जमाना था, चूड़ी निकालना यानी महिला के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी, लेकिन उनके लिए ''वंदे मातरम्'' वह भावना थी, उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक ''वंदे मातरम्'' प्रतिबंध नहीं हटेगा, मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं रहे थे, उनको कोड़े की सजा होती थी, छोटी-छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और उन दिनों खास करके बंगाल की गलियों में लगातार ''वंदे मातरम्'' के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया

था और उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में -

जाए जाबे जीवोनो चोले,
जाए जाबे जीवोनो चोले,
जोगोतो माझे तोमार काँधे
''वंदे मातरम्'' बोले

अर्थात्- हे मां संसार में तुम्हारा काम करते और ''वंदे मातरम्'' कहते जीवन भी चला जाए, तो वह जीवन भी धन्य है, यह बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे थे। यह गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था और उन बच्चों की हिम्मत ने देश को हिम्मत दी थी। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी। 1905 में हरितपुर के एक गांव में बहुत छोटी-छोटी उम्र के बच्चे, जब ''वंदे मातरम्'' के नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों ने बेरहमी से उन पर कोड़े मारे थे। हर एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना अत्याचार हुआ था। 1906 में नागपुर में नील सिटी हाई स्कूल के उन बच्चों पर भी अंग्रेजों ने ऐसे ही जुल्म किए थे। गुनाह यही था कि वह एक स्वर से ''वंदे मातरम्'' बोल करके खड़े हो गए थे। उन्होंने ''वंदे मातरम्'' के लिए, मंत्र का महात्म्य अपनी ताकत से सिद्ध करने का प्रयास किया था। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक ''वंदे मातरम्'' ''वंदे मातरम्'' ''वंदे मातरम्'', यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, रोशन सिंह, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास अनगिनत जिन्होंने ''वंदे मातरम्'' कहते-कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए यह अलग-अलग जेलों में होता था, अलग-अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे। जिन पर जुल्म हो रहा था, उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इन सबका मंत्र एक ही था, ''वंदे मातरम्''। चटगांव की स्वराज क्रांति जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, वह भी इतिहास के चमकते हुए नाम हैं। हरगोपाल कौल, पुलिन विकाश घोष, त्रिपुर सेन इन सबने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मास्टर सूर्य सेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वह शब्द था ''वंदे मातरम्''।

हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए, दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता, जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि-कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हों, दुनिया में ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता, जो ''वंदे मातरम्'' है। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे, जो इस प्रकार के भाव गीत की रचना कर सकते थे। यह विश्व के लिए अजूबा है, हमें गर्व से कहना चाहिए, तो दुनिया भी मानना शुरू करेगी। यह हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, यह बलिदान का मंत्र था, यह ऊर्जा का मंत्र था, यह सात्विकता का मंत्र था, यह समर्पण का मंत्र था, यह त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का यह मंत्र था और वह मंत्र ''वंदे मातरम्'' था। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था -

एक कार्ये सोंपियाछि सहस्र जीवन— ''वंदे मातरम्''

अर्थात्- एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, ''वंदे मातरम्''।

उसी कालखंड में ''वंदे मातरम्'' की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग-अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वह लंदन का इंडिया हाउस वीर सावरकर जी ने वहां ''वंदे मातरम्'' गीत गाया और वहां यह गीत बार-बार गूंजता था। देश के लिए जीने-मरने वालों के लिए वह एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय विपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अखबार निकाले, उस अखबार का नाम भी उन्होंने ''वंदे मातरम्'' रखा। यानी डगर-डगर पर अंग्रेजों के नींद हराम करने के लिए ''वंदे मातरम्'' काफी हो जाता था और इसलिए उन्होंने इस नाम को रखा। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी, तो मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने ''वंदे मातरम्'' रखा!

''वंदे मातरम्'' ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस के डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े-बड़े शिप उस पर भी ''वंदे मातरम्'' लिखने की परंपरा बन गई और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरह विस्तार होता गया।

मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बनाया, तो उस पर भी लिखा था ''वंदे मातरम्''। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने ''वंदे मातरम्'' को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई

तमिल देशभक्ति गीतों में ''वंदे मातरम्'' की श्रद्धा साफ-साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को लगता है, तमिलनाडु के लोगों को पता हो, लेकिन सभी लोगों को यह बात का पता ना हो कि भारत का ध्वज गीत वी. सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत का वर्णन जिस पर ''वंदे मातरम्'' लिखा हुआ था, तमिल में इस ध्वज गीत का शीर्षक था-

Thayin manikodi pareer, thazhndu panintu Pukazhnthida Vareer!

अर्थात्- देश प्रेमियों दर्शन कर लो, सविनय अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो।

''वंदे मातरम्'' पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी, वह भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में जो लिखा था, उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था,

गीत ''वंदे मातरम्'' जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुईं, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया।

गांधी जी आगे लिखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह लिखते हैं यह 1905 की बात है। उन्होंने लिखा,

''यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है, जैसे यह हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है।''

जो ''वंदे मातरम्'' 1905 में महात्मा गांधी

को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में, जो भी देश के लिए जीता-जागता, जिस देश के लिए जागता था, उन सबके लिए ''वंदे मातरम्'' की ताकत बहुत बड़ी थी। ''वंदे मातरम्'' इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? ''वंदे मातरम्'' के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? यह अन्याय क्यों हुआ? वह कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? जिसने ''वंदे मातरम्'' जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम ''वंदे मातरम्'' के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है। जिसकी वजह से ''वंदे मातरम्'' के साथ विश्वासघात किया गया। ''वंदे मातरम्'' के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को ''वंदे मातरम्'' के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और ''वंदे मातरम्'' के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने ''वंदे मातरम्'' की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि ''वंदे मातरम्'' भी यह जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, ''वंदे मातरम्'' की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का क्वोट पढ़ता हूं, नेहरू जी कहते हैं-

मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं-

मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे।

इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें ''वंदे मातरम्'' के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था, पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने-कोने में प्रभात फेरियां निकालीं, ''वंदे मातरम्'' गीत गाया लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने ''वंदे मातरम्'' पर समझौता कर लिया। ''वंदे मातरम्'' के टुकड़े करने के फैसले में ''वंदे मातरम्'' के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया और कांग्रेस का यह तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था।

तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस ''वंदे मातरम्'' के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है, कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नीतियां वैसी की वैसी ही हैं और इतना ही नहीं INC चलते-चलते MMC हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन-जिन के नाम के साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब, ''वंदे मातरम्'' पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं।

किसी भी राष्ट्र का चरित्र उसके जीवटता उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा, जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती हैं, उजागर होती हैं और सच्चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती हैं। जब कसौटी का काल आता है, तब ही यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश के प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता, वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब-जब संकट आए, देश हर बार ''वंदे मातरम्'' की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया, जाने दो। लेकिन आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है। तिरंगे झंडे फहरते हैं। एक जमाना था, जब देश में खाद्य का संकट आया, वही ''वंदे मातरम्'' का भाव था, मेरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए और उसके पीछे भाव वही है ''वंदे मातरम्''। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोप दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही ''वंदे मातरम्'' की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही ''वंदे मातरम्'' का भाव था, देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा लहराता रहा, विजय श्री प्राप्त करता रहा। कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ा।

यह राष्ट्र की शक्ति है, यह राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है। यह चेतना प्रवाह है, यह संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। यह ''वंदे मातरम्'' हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए और हम उसके प्रति समर्पित होते चलें और मैंने पहले कहा हम लोगों पर तो कर्ज है ''वंदे मातरम्'' का, वही ''वंदे मातरम्'' है, जिसने वह रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। ''वंदे मातरम्'' के भाव की वो ताकत है। ''वंदे मातरम्'' यह सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, यह हमारे लिए प्रेरणा है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, उसको पूरा करना है। ''वंदे मातरम्'' हमारी प्रेरणा है।

हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं, समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव की ताकत आज भी हममें मौजूद है और ''वंदे मातरम्'' हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का, आजाद भारत के सपने को सींचा था वंदे भारत की भावना ने, वंदे भारत की भावना ने, समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा ''वंदे मातरम्'' के भाव, उसी भावनाओं को लेकर के हमें आगे चलना है। और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, 2047 में देश विकसित भारत बन कर रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र और इसी संकल्प के साथ ''वंदे मातरम्'' हमें प्रेरणा देता रहे, ''वंदे मातरम्'' का हम ऋण स्वीकार करें, ''वंदे मातरम्'' की भावनाओं को लेकर के चलें, देशवासियों को साथ लेकर के चलें, हम सब मिलकर के चलें, इस सपने को पूरा करें, देश के अंदर वह भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। ▪

''वंदे मातरम्'' राष्ट्र पुनर्निर्माण का आधार - अमित शाह

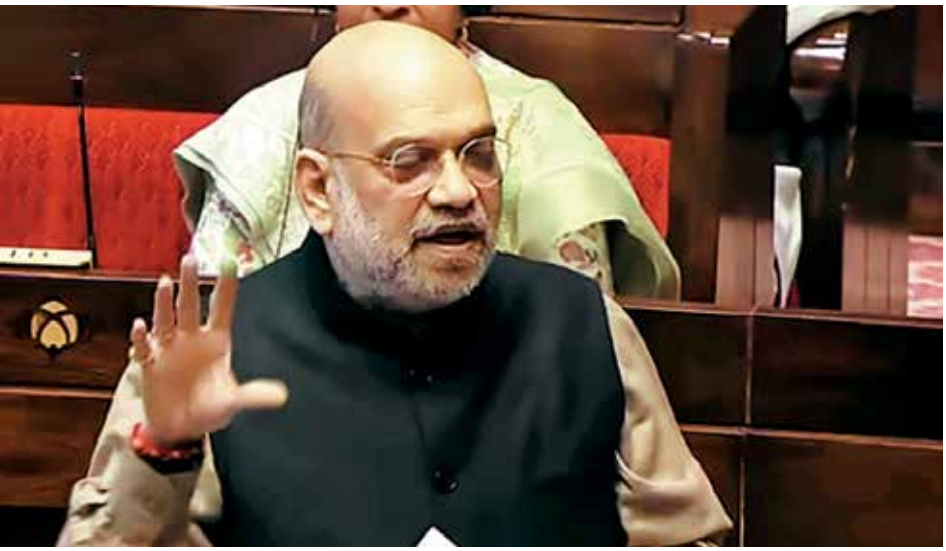

भारत की मूल सनातन चेतना को जगाने का कार्य ''वंदे मातरम्'' ने किया और इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने इसे संघर्ष का आधार बनाया। कई सेनानी जब फांसी के तख्ते पर जाते थे, तब उनके अंतिम शब्द ''वंदे मातरम्'' ही होते थे।

- **''वंदे मातरम् राष्ट्र के प्रति समर्पण का माध्यम आजादी के आंदोलन में भी था, आज भी है और 2047 में विकसित भारत के निर्माण के समय भी रहेगा।**
- **''वंदे मातरम्'' केवल देशभक्ति का गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है।**
- **स्वतंत्रता संग्राम में ''वंदे मातरम्'' ने क्रांतिकारियों और सैनिकों को प्रेरित किया और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में सम्मान दिया गया। कांग्रेस ने ''वंदे मातरम्'' की महिमा को राजनीतिक रूप से कम करने की कोशिश की।**

वंदे मातरम् के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में विशेष कार्यक्रम, डाक टिकट, सिक्के, प्रदर्शनी और सामूहिक गान आयोजित किए जा रहे हैं। ''वंदे मातरम्'' आज भी राष्ट्र निर्माण और युवा पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति जागृत करने का माध्यम है।

सदन में जब ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा हो रही थी, तब कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि आखिर इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता क्यों है। ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा और उसके प्रति समर्पण की आवश्यकता आज ही नहीं, आजादी के आंदोलन के समय भी थी और 2047 में विकसित भारत के निर्माण के दौरान भी रहेगी। यह अमर रचना मातृभूमि के प्रति भक्ति, समर्पण और कर्तव्य बोध जगाने वाली कृति है। जिन लोगों को ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा की आवश्यकता समझ नहीं आ रही, उन्हें अपनी समझ पर पुनः विचार करने की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ''वंदे मातरम्'' की चर्चा हो रही है। वे इसकी महिमा को चुनाव से जोड़कर कम करना चाहते हैं। यह सही है कि आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल में जन्मे, गीत वहीं लिखा गया और आनंद मठ की पृष्ठभूमि भी बंगाल की थी, लेकिन ''वंदे मातरम्'' का उदय केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। यह पूरे देश और दुनिया भर में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बना।

आज भी सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के होंठों पर ''वंदे मातरम्'' ही रहता है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी अपने सर्वोच्च बलिदान के समय इसी मंत्र को स्मरण करते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान ''वंदे मातरम्'' गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का स्वर बन चुका था और अनेक क्रांतिकारियों को यह प्रेरणा देता था कि अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर राष्ट्र की सेवा करें। यह गीत पीढ़ियों से लोगों को अपनी संस्कृति के मार्ग पर चलने और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहा है।

संसद के दोनों सदनों में होने वाली इस चर्चा से बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली पीढ़ियां ''वंदे मातरम्'' के महत्व को समझ सकेंगी और राष्ट्र पुनर्निर्माण में इसे प्रेरणा स्वरूप अपनाएंगी। 7 नवंबर 1875, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ''वंदे मातरम्'' का प्रथम सार्वजनिक प्रकाशन हुआ, जिसे अक्षय नवमी या जगद्धात्री पूजा के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में इसे एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना माना गया लेकिन धीरे-धीरे यह देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनकर आजादी के आंदोलन का मार्गदर्शक बना।

सदियों तक इस्लामिक आक्रमणों का विरोध करने वाली संस्कृति और फिर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए नए जीवन-व्यवहार के बीच, बंकिम बाबू ने इस गीत के माध्यम से भारत की मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मातृभूमि की उपासना की परंपरा को पुनः स्थापित किया।

उस समय न सोशल मीडिया था, न प्रचार के साधन। उल्टा अंग्रेजी शासन ''वंदे मातरम्'' बोलने पर प्रतिबंध लगाता था, कोड़े

मारता था, जेल में डालता था। फिर भी यह गीत सब प्रतिबंधों को पार करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया और भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए पुनर्जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, कृषि व्यवस्थाएं और शिक्षा प्रणालियां नष्ट की गई, लेकिन भारतीय संस्कृति की आत्मा को कोई कमजोर नहीं कर पाया। आवश्यकता केवल उस भावना को जागृत करने की थी, और वही कार्य ''वंदे मातरम्'' ने किया। यह गीत देशभर में फैलता हुआ अंडमान-निकोबार की जेलों तक पहुँचा, जिसे न अंग्रेज रोक पाए न उनके समर्थक। ''वंदे मातरम्'' ने उस राष्ट्र को पुनर्जीवित किया जिसने अपनी दिव्य शक्ति को भुला दिया था। महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जन्म का मंत्र कहा और यह भी कहा कि ईश्वर ने देश के लिए आवश्यक इस मंत्र को साकार करने हेतु ही बंकिम बाबू को जन्म दिया। उनका विचार आजादी के आंदोलन का नारा बना और पीढ़ियों का प्रेरणा स्त्रोत भी।

हमारा देश दुनिया में अनूठा है। कई देशों की सीमाएं युद्धों, संधियों या अधिनियमों से बनी हैं, लेकिन भारत की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की हैं। इसी सांस्कृतिक आधार ने भारत को जोड़े रखा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार गुलामी के काल में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जागृत किया। पूरे देश को देखें तो स्पष्ट होता है कि भारत को जोड़ने वाली असली शक्ति हमारी संस्कृति है। यही सांस्कृतिक आधार वह मंत्र है जिसने ''वंदे मातरम्'' के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। जब अंग्रेजों ने ''वंदे मातरम्'' पर कई प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने पत्र में लिखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि उनका पूरा साहित्य नदी में बहा दिया जाए, क्योंकि ''वंदे मातरम्'' अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह गीत लोगों के हृदय में स्थान बनाएगा और भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र बनेगा। आज यह स्पष्ट दिख रहा है कि बंकिम बाबू के शब्द सत्य साबित हुए हैं। देर से ही सही, आज पूरा राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र वाद की भावना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारत माता की संताने मानते हैं कि यह देश जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी मां है और उसी भावना की अभिव्यक्ति ''वंदे मातरम्'' है।

''वंदे मातरम्'' की रचना में भारत माता के स्वरूप का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इसमें जल, फल और समृद्धि की दायिनी भारत माता का वर्णन है। मन को प्रफुल्लित करने वाली पुष्पों की शोभा भी भारत माता से जोड़ी गई है। इसमें सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के स्वरूप को भारत माता बताया गया है। ज्ञान, समृद्धि और रक्षा की शक्ति भारत माता की कृपा से ही मिल सकती है, इसलिए बार-बार प्रणाम करने की भावना इस गीत में व्यक्त होती है। बंकिम बाबू ने दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेधा को भारत माता का आशीर्वाद बताया है। यह विचार भले उन्होंने आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले प्रस्तुत किया हो, लेकिन इसकी जड़ें बहुत प्राचीन हैं। रामायण में भगवान श्री राम ने लंका पर विजय के बाद भी मातृभूमि का त्याग नहीं किया और कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी महान होती हैं। आचार्य शंकर और आचार्य चाणक्य ने भी मातृभूमि के महिमा मंडन को सर्वोच्च स्थान दिया और हमारी पहचान को मातृभूमि के साथ जोड़ा।

वही हमें भाषा, संस्कृति और जीवन को उन्नत करने का अवसर देती है। गुलामी के घने अंधकार में इस चिर पुरातन भाव को बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया। ''वंदे मातरम्'' के उद्घोष ने जनमानस में स्वराज की भावना जगाई और गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का कार्य किया। महर्षि अरविंद ने ''वंदे मातरम्'' को गीत नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बताया। बताया कि ''वंदे मातरम्'' शरीर में ऊर्जा जगाता है, भावनाओं और विचारों को शुद्ध करता है और चेतना को जागृत करता है। यह केवल देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आव्हान है।

भारत की मूल सनातन चेतना को जगाने का कार्य ''वंदे मातरम्'' ने किया और इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने इसे संघर्ष का आधार बनाया। कई सेनानी जब फांसी के तख्ते पर जाते थे, तब उनके अंतिम शब्द ''वंदे मातरम्'' ही होते थे। स्वदेशी आंदोलन का आह्वान हो, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की पुकार हो, राष्ट्रीय शिक्षा का संदेश हो या राष्ट्रभक्ति का उत्साह, हर चरण में इस देश ने ''वंदे मातरम् का उद्घोष सुना और महसूस किया। पंजाब के गदर आंदोलन में ''वंदे मातरम्'' शीर्षक से कई पर्चे बांटे गए। महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव के दौरान ''वंदे मातरम्'' के विशेषांक बेचे और वितरित किए जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने इसका तमिल अनुवाद किया और हिंद महासागर तक क्रांति की चेतना को जागृत किया। 1907 में कोलकाता में ''वंदे मातरम्'' नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना और महर्षि अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजा भी हुई और अंत में पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी ''वंदे मातरम्'' का सम्मान किया। 1896 में गुरुदेव टैगोर ने इसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया और 1905 में वाराणसी अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण ''वंदे मातरम्'' का गायन किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तब सुबह पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सरदार पटेल के आग्रह पर आकाशवाणी से ''वंदे मातरम्'' का गायन किया। इसी भावना के आधार पर संविधान सभा की अंतिम बैठक में, अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में ''वंदे मातरम्'' को राष्ट्रगान के समकक्ष सम्मान देते हुए राष्ट्रगीत घोषित किया गया।

कांग्रेस के कई सदस्य पूछ रहे थे कि ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा क्यों की जा रही है और इसे राजनीतिक हथकंडा बता रहे थे। ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा से बचने की यह मानसिकता नई नहीं है। यह ''वंदे मातरम्'' का 150 वां वर्ष है और हमारे देश में किसी भी महान रचना के महत्वपूर्ण वर्ष को सम्मान दिया जाता है। जब ''वंदे मातरम् के पचास वर्ष पूरे हुए, तब देश आजाद नहीं था। 1937 में इसकी स्वर्ण जयंती पर जवाहरलाल नेहरू ने इसे दो अंतरों में सीमित कर दिया। यह ''वंदे मातरम्'' के महिमा मंडन को रोकने की शुरुआत थी और यही क्रम आगे तुष्टिकरण की नीति तक पहुंचा जिसने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया।

यदि ''वंदे मातरम्'' को सीमित करने का निर्णय न लिया जाता तो देश का विभाजन न होता। पचास वर्ष बाद, जब ''वंदे मातरम्'' के सौ वर्ष पूरे हुए, तब इसके सम्मान की कोई

बात ही नहीं हुई क्योंकि देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। लाखों विपक्षी कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को जेल में बंद कर दिया गया। अखबारों पर ताले लगा दिए गए और आकाशवाणी पर कई कलाकारों की आवाजें बंद कर दी गईं। जब ''वंदे मातरम्'' 100 वर्ष का हुआ, तब पूरा देश मानो एक बंदी शिविर बन गया था।

''वंदे मातरम्'' के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के दोनों सदस्य अनुपस्थित रहे। जिस कांग्रेस के अधिवेशनों की शुरुआत कभी गुरुवर टैगोर जैसे लोगों के ''वंदे मातरम्'' गाने से होती थी, आज वही कांग्रेस इस चर्चा से बचती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस नेतृत्व तक ''वंदे मातरम्'' का विरोध उनकी सोच में बना हुआ है। कांग्रेस की एक प्रमुख नेत्री ने कहा कि ''वंदे मातरम्'' पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गीत को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा बताया और जिसे बिपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रधर्म की अभिव्यक्ति कहा, उसी ''वंदे मातरम्'' को काटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल एवं उनके नेता ''वंदे मातरम्'' का अनादर करते हैं जो निंदनीय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ''वंदे मातरम्'' ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और विश्व में भारत की राष्ट्रीय चेतना का परिचय कराया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज बनाया था, उस पर स्वर्णिम अक्षरों में केवल एक ही शब्द अंकित था, ''वंदे मातरम्''। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गुलामी के कठिन काल में जब भारतीय हॉकी टीम को प्रेरणा की आवश्यकता थी, तब कोच ने पूरी टीम को एक पंक्ति में खड़ा कर भावपूर्ण स्वर में ''वंदे मातरम्'' का उच्चारण कराया और टीम स्वर्ण पदक जीतकर लौटी।

भाजपा की स्थापना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के साथ हुई। पार्टी का मूल विचार यह रहा है कि भारत अपनी मूल संस्कृति और मूल विचारों के आधार पर आगे बढ़े, न कि पश्चिमी संस्कृति की दिशा में बहके। संसद में एक समय ''वंदे मातरम्'' का गान बंद करा दिया गया था। 1992 में भाजपा सांसद राम नाइक ने अल्प अवधि चर्चा के माध्यम से ''वंदे मातरम्'' का गान पुनः शुरू करने का विषय उठाया। उस समय प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि संविधान सभा ने जिसे स्वीकार किया है उसका गान इस सदन में अवश्य होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा ने सर्वसम्मति से ''वंदे मातरम्'' के गान की पुनः शुरुआत की। उस समय भी कई सदस्य ''वंदे मातरम्'' गाने से इनकार करते थे। कुछ सदस्य ''वंदे मातरम्'' का गान शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर चले जाते थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य ''वंदे मातरम्'' के गान के समय सम्मानपूर्वक खड़े होने में कभी पीछे नहीं हट सकता। कांग्रेस के जिन सदस्यों ने ''वंदे मातरम्'' गाने से इनकार किया, उनके नाम वे सदन के पटल पर रखने वाले हैं और अनुरोध करते हैं कि वे इस चर्चा का हिस्सा बनाए जाएं ताकि देश को यह तथ्य ज्ञात हो सके।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 130 वीं जयंती पर डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया। आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से आग्रह किया कि तिरंगा फहराते समय ''वंदे मातरम्'' का उद्घोष अवश्य किया जाए। ''वंदे मातरम्'' के 150 वर्षों को भारत सरकार पूरे वर्ष भव्य रूप से मना रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी रूपरेखा को अनुमोदित किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को भारत माता को पुष्पांजलि देकर इस वर्ष का शुभारंभ किया। इसका पहला चरण नवंबर में पूरा हुआ। दूसरा चरण जनवरी 2026 में, तीसरा अगस्त 2026 में और चौथा नवंबर 2026 में होगा। केंद्रीय सरकार ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। 75 वादकों द्वारा ''वंदे मातरम्'' नाद एकम रूप अनेकम शीर्षक से विशेष प्रस्तुति तैयार की गई। 7 नवंबर को देशभर में सामूहिक ''वंदे मातरम्'' का गान हुआ। इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी प्रत्येक जिला केंद्र और आवश्यकता अनुसार तहसील स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शनी को डिजिटल माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

आकाशवाणी, दूरदर्शन और एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा विभिन्न शहरों में चर्चाओं का आयोजन होगा। सभी भारतीय दूतावासों में ''वंदे मातरम्'' आधारित सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। ''वंदे मातरम्'' सैल्यूट टू मदर अर्थ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। राजमार्गों पर ''वंदे मातरम्'' के इतिहास को दर्शाने वाले भित्ति चित्र लगाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से घोषणाएं होंगी और ''वंदे मातरम्'' तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर लघु फिल्में भी बनाई जा रही हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंचप्रण का आव्हान किया जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता और अखंडता की रक्षा और नागरिक कर्तव्य का विस्तार शामिल है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया। गांव-गांव में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद किया गया, अनेक अनदेखे योद्धाओं के स्मारक बनाए गए और युवाओं को 1857 से 1947 तक के संघर्ष से परिचित कराया गया। अमृत काल के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प रखा कि आजादी की शताब्दी तक भारत हर क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनेगा। यह किसी एक व्यक्ति या दल का संकल्प नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। दैवयोग से ''वंदे मातरम्'' के 150 वें वर्ष के साथ यह संकल्प और अधिक सशक्त होता है, क्योंकि ''वंदे मातरम्'' ही राष्ट्रभक्ति को पुनः जागृत करने का माध्यम बनेगा। ''वंदे मातरम्'' कभी कालातीत नहीं होगा। जिस समय इसकी रचना हुई थी, तब भी इसकी उतनी ही आवश्यकता थी जितनी आज है।

स्वतंत्रता संग्राम में जिसने देश को एक किया, वही ''वंदे मातरम्'' अमृत काल में देश को विकसित और महान बनाने का प्रेरक बनेगा। यह सदन का दायित्व है कि बच्चों और युवाओं के मन मे ''वंदे मातरम्'' की भावना को पुनः स्थापित किया जाए, उन्हें राष्ट्रभक्ति के इस उद्गार की शक्ति समझाई जाए और आने वाली पीढ़ी को ''वंदे मातरम्'' के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए। ▪

प्रदेश में अकल्पनीय विकास- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश में हुए विकास कार्यों की जनता साक्षी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदल दिया है। प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत है, अकल्पनीय है। मध्यप्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। इससे प्रदेश के विकास की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर विकास की धारा से जुड़कर जीवन को चुना है। लाल सलाम के खात्मे के लिए बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह निःसंदेह अद्भुत है। सरकार ने सभी क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास और सेवा का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां और अवसर भी हमारे लिए अनुकूल होते जा रहे हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन-बेतवा, पीकेसी के बाद ताप्ती मेगा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज परियोजना की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत ही मंदाकिनी-चित्रकूट के नाम पर उप परियोजना का नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे चित्रकूट धाम के आसपास भी पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, साथ ही बिजली उत्पादन भी होगा। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सरकार अगले पांच साल में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि रकबे को सिंचित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

प्रदेश में 1988-90 से नक्सलियों की गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। कभी ऐसी भी स्थिति रही कि राज्य में पुलिस की बसों को आग के हवाले कर दिया गया। एक मंत्री की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। जबकि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। आज केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में तय की गई डेडलाइन के अंदर ही राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश की भूमि से नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मध्यप्रदेश 35 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ। इस अभियान में कुछ जवानों को शहादत भी हुई। पिछले साल प्रमोशन मिलने के बाद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए। दो नक्सलियों के सरेंडर के साथ मध्य प्रदेश में नक्सलियों की संख्या शून्य हो गई है। राज्य सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई। 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ऐसा तंत्र विकसित करेंगे, जिससे दोबारा नक्सलवादी मूवमेंट स्थापित न हो पाए। सभी पड़ोसी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय किया।

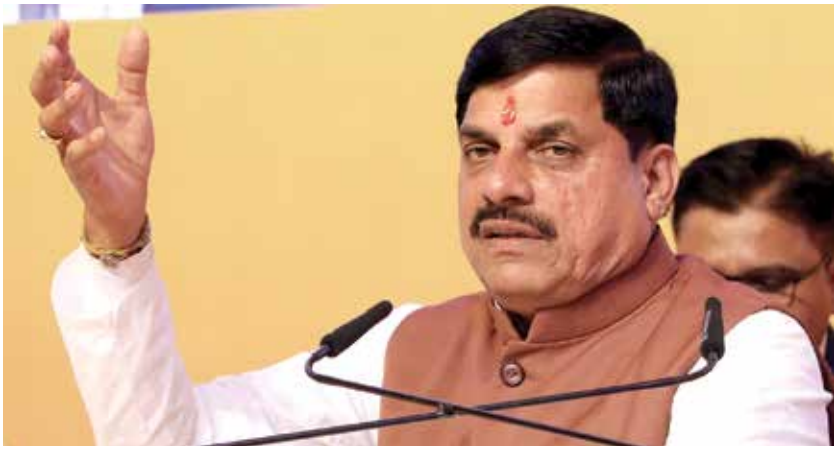

प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन-बेतवा, पीकेसी के बाद ताप्ती मेगा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज परियोजना की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत ही मंदाकिनी-चित्रकूट के नाम पर उप परियोजना का नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू हुआ है। पार्वती-कालीसिंध और चंबल परियोजना के समझौते के बाद अब मध्यप्रदेश और राजस्थान को पर्याप्त जल मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती वॉटर रीचार्ज परियोजना पर भी कार्य हो रहा है। एक लाख करोड़ की पीकेसी परियोजना में 90 हजार करोड़ भारत सरकार दे रही है। इसी प्रकार ताप्ती परियोजना के लिए भी 70 हजार करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। उज्जैन में पहले सिंहस्थ हुए, लेकिन श्रद्धालुओं को गंभीर नदी के जल से स्नान कराया गया। वर्ष 2016 में नर्मदा के जल से स्नान का प्रबंध कराया, लेकिन आगामी 2028 के सिंहस्थ के लिए 800 करोड़ लागत से नई योजना बनाई है। अब श्रद्धालु क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे। राज्य के अंदर पहली बार दो नदियों- गंभीर और कान्ह को अंडर डक्ट के माध्यम से लिंक किया जा रहा है।

पहले भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी। भूतो न भविष्यति इसी साल फरवरी में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) हुई। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से भी निवेश आया है। इसी का परिणाम है कि निवाड़ी जैसे छोटे जिले में इस्पात कारखाना खुल रहा है। झाबुआ में खाद बनाया जा रहा है। नीमच में भारत ही नहीं दुनिया का पंप स्टोरेज बना है, जिसका कार्य दो साल में पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वीकृत 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला पार्क का अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्यप्रदेश के धार में भूमिपूजन किया है। राज्य सरकार ने इसमें भूमि आवंटन भी कर दिया है। विक्रम उद्योगपुरी में दवा कंपनियों ने इंडस्ट्री लगाकर उत्पादन शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब प्रदेश में सरकारी-निजी कुल मिलाकर 52 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज

और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1 रुपए लीज पर जमीन दे रही है।

दो सालों में ही हुकुमचंद मिल के मजदूरों के बकाये का विवाद खत्म कराया। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाते हुए जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। इंदौर-उज्जैन, भोपाल-नर्मदापुरम को मेट्रोपोलिटन एरिया बनाने की योजना बनाई गई। हमारे औद्योगिक केंद्र मेट्रोपोलिटन एरिया के विकास के मुख्य आधार बनेंगे। प्रदेश में नई एविएशन पॉलिसी लेकर आए हैं। इसके तहत प्रदेश में पहली बार इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज शुरू की गई हैं। रीवा से इंदौर और दिल्ली के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हो गई है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास तेजी से जारी है। चित्रकूट धाम और ओरछा धाम के विकास कार्य जारी हैं। हमने एक बगिया मां के नाम और गंगोत्री योजना शुरू की।

देश में सबसे सस्ती बिजली मध्यप्रदेश दे रहा है। ओंकारेश्वर, नीमच में सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुरैना में स्थापित हो रहा सोलर प्लांट मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तरप्रदेश को भी बिजली उपलब्ध कराएगा। केन्द्र सरकार ने साइबर तहसील का पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है। बटवारा, ई-नामांतरण जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया। सड़कों के किनारे मुरम खुदाई से बने गड्ढों को जल संचयन संरचना के रूप में विकसित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। यहां 250 से अधिक नदियां बहती हैं। बूंद-बूंद पानी को सहेजने की योजना बना रहे हैं।

गौ संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है। दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। गोपालकों को 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी गोशालाएं खोलने पर भी अनुदान मिलेगा। गोशालाओं के लिए 125 एकड़ भूमि भी दी जाएगी।

हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं। प्रदेश में कचरे और पराली से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कई नामी कम्पनियों ने भी रूचि व्यक्त की है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। आईटी सिटी और एआई सिटी तैयार करने की योजना है। प्रदेश में जल्द ही ई-बसें भी शुरू की जाएंगी। गरीब कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। बजट को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख 54 हजार रुपए तक बढ़ाया गया है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, सोयाबीन की खरीद के लिए भावांतर योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को दी जाने वाली मासिक राशि भी बढ़ा दी गई है। अब बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।

द ''ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया'' भारतीयों को समर्पित है - पीएम मोदी

मुझे "Great Honour Nishan of Ethiopia" के रूप में, इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति-प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना, बहुत गौरव की बात है। सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूँ ।

यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने भारत-इथियोपिया साझेदारी को आकार दिया-1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हों, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हों, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया।

इस अवसर पर मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता, और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉ. अबी के कुशल हाथों में हैं।

अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ, वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इन्क्लूसिव डेवलपमेंट हो या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की हृदय से सराहना करता हूँ।

भारत में हमारा मानना रहा है कि ''सा विद्या, या विमुक्तये''। यानि knowledge liberates। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है, और इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने इन्हे यहाँ आकर्षित किया और उन्हे यहाँ के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई Indian Faculty Members Ethiopian Universities और Higher Educational Institutions में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

भविष्य उन्हीं partnerships का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हों। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी। ▪

प्रदेश में विकास नई ऊंचाइयों पर हेमंत खंडेलवाल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार निरोधी कदम उठाए हैं। प्रदेश में गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य हुए हैं। राज्य सरकार 2047 के विकसित मध्यप्रदेश के लिए कार्य कर रही है। जनजातीय कल्याण के लिए 40 हजार करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान किया है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाएं स्थापित करने के साथ उनके नाम पर कैबिनेट की गई। प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरियों के पद भरे गए। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क की सौगात मिली है। राजधानी में सम्राट विक्रमादित्य और राजाभोज के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश में एयर एंबुलेंस की शुरुआत की गई है।

डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रशासन को मूल आधार मानते हुए हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। गरीब, युवाओं, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनके कल्याण के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जवाबदेही की व्यवस्था को सुधारने का काम पारदर्शी तरीके से किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की पूर्ति में योगदान देते हुए डॉ. मोहन यादव की सरकार विकसित मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

बीते दो सालों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान और उत्थान को लेकर बजट में 40,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया और वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं स्थापित की तथा राजा भभूत सिंह जैसे नायकों के नाम पर कैबिनेट आयोजित करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। महिला सशक्तिकरण में नई क्रांति कही जाने वाली लाड़ली बहना योजना में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये कर दी गई है। देवी अहिल्या और नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है तथा महिला उद्यमियों के लिए लगभग 275 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की। नए स्टार्टअप्स के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख तक की सहायता दी।

डॉ. मोहन यादव की सरकार ने बीते दो सालों में हर क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दृष्टि से बीते दो सालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। निवेश बढ़ाने के लिए 18 नई नीतियों की शुरुआत की है और नया निवेश ईको सिस्टम बनाया है। धार में पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे 3 लाख रोजगार पैदा होंगे तथा 6 लाख कपास उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से प्रदेश को 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 23 लाख रोजगार पैदा होंगे। 8.57 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आकार ले चुका है और मध्यप्रदेश, देश में तीसरा सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव हासिल करने वाला राज्य बन गया है। संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में अगर देखें, तो प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज सहित नौ महापुरुषों के नाम पर राजधानी में द्वार स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओंकारेश्वर, विक्रमोत्सव, राम वनगमन पथ, श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थल और मां क्षिप्रा का शुद्धिकरण तथा घाट निर्माण के निर्णय इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार ने सिंहस्थ-2028 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस जैसा नया प्रयोग करते हुए 109 से अधिक लोगों का एयरलिफ्ट किया है। 12655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 448 संजीवनी क्लीनिक तथा 72 मोबाइल मेडिकल क्लीनिक की स्थापना सरकार ने की है। प्रदेश सरकार ने सागर, मुरैना, शहडोल, बालाघाट और नर्मदापुरम में आयुष मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है जो प्रदेश के नागरिकों को उत्कृष्ट आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पूर्ण हुए दो वर्ष मध्यप्रदेश के विकास, सुशासन और सेवा की नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने जो व्यापक कदम उठाए हैं, उन्होंने प्रदेश को नई गति और नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय नायकों के सम्मान में जनजातीय वीरों के स्थलों पर कैबिनेट बैठकें कर एक अनोखी परंपरा स्थापित की है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करना सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास हुए हैं। अब तक लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार एवं निवेश के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के तहत ओंकारेश्वर, विक्रमादित्य उत्सव, राम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण लीला स्थल जैसी परियोजनाओं को नई ऊर्जा मिली है। मां क्षिप्रा नदी शुद्धिकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अजा-अजजा मोर्चा सहित सभी मोर्चे इन दो वर्षों में हुए जनहितैषी कार्यों को पारदर्शिता और तत्परता के साथ जनता तक पहुँचाएँ। कार्यकर्ता सरकार के सभी जनकल्याणकारी कार्यों को बूथ स्तर तक लेकर जाएँ। इस बार 'मन की बात' कार्यक्रम के पश्चात 15 मिनट तक प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार, पिछले तीन महीनों में कैबिनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा संगठन द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों की एक विस्तृत पीपीटी और पीडीएफ रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे बूथ स्तर तक ले जाकर जन-जन में सरकार की उपलब्धियाँ पहुंचाई जाएँगी। हम सब मिलकर जनहित की योजनाओं को जनता तक पहुँचाएँगे और आगामी कार्यक्रमों को पूर्ण सफलता दिलाएँगे। ▪

शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है - अमित शाह

झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई, इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। अभी-अभी चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, यह कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है

- **विपक्षी पार्टियों ने CAA के बारे में झूठ फैलाया, मोदी जी ने CAA लाकर दशकों से हुई शासन की गलती का तर्पण किया।**
- **1951 से 2011 तक की जनगणना में जो सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में असमानता दिखती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है।**

घुसपैठ, जनसांख्यिकी का बदलाव और लोकतंत्र, ये तीनों विषय जब तक प्रत्येक भारतीय और विशेषकर युवा, जिसने 50-60-75 साल तक देश में जीना है, वो नहीं समझता है, इसकी समस्या से परिचित नहीं होता है, तो हम हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं, मुझे मालूम है कुछ चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी। मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा, तो मेरे दायित्व के साथ मैं छल कर रहा हूं।

इस देश में 1951 में, 1971 में, 1991 में और 2011 में जनगणना हुई। अब जो मैं बोल रहा हूं जनगणना के रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जनगणना में शुरू से, आजादी के बाद तुरंत से धर्म पूछने की एक परंपरा है, जनगणना में बाकी सब पूछते हैं, उसमें आप कौन से धर्म के अनुयायी हो, वह पूछा जाता है, मुझे मालूम नहीं है उस वक्त1951 में क्यों यह निर्णय हुआ होगा? मगर निर्णय हमने नहीं किया है, आप सभी को मालूम है 1951 में मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी, उस वक्त जब यह जनगणना का निर्णय हुआ, हम निर्णायक तो नहीं ही थे। आंकड़े बताना चाहता हूं, 1951 की जनगणना में हिंदू 84 प्रतिशत थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8 प्रतिशत थी, 1971 में 82 प्रतिशत हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11 प्रतिशत हुई, 1991 में 81 प्रतिशत हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12 प्रतिशत हुई और 2011 में 79 प्रतिशत हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2 प्रतिशत हुई, इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा कि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात की और इसके रेफरेंस में बाद में बताऊंगा, हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन ना हुआ होता, तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु देश का विभाजन क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ है, तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 1951 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा, तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोत्तरी 24.6 प्रतिशत के दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5 प्रतिशत की दर से कमी हुई है, अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है यह घुसपैठ के कारण हुआ है, जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ और वह दोनों जगह से घुसपैठ के कारण यह आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया और हमारे पड़ोसी देश, हमारे ही देश का एक हिस्सा जिसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, उसमें स्थिति क्या हुई, वो भी देखना चाहिए।

देश आजाद हुआ 1951 में तब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 13 प्रतिशत थी, अन्य माइनॉरिटी 1.2 प्रतिशत थे और अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.73 प्रतिशत बची है, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22 प्रतिशत थी, अब वहां पर 7.9 प्रतिशत बची है और अफगानिस्तान में 2,20,000 हिंदू सिख थे, आज 150 बचे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर है, यह सारे जो हिंदू कम हुए, वह मतांतरित नहीं हुए। सारे नहीं हुए, बहुतों ने भारत में आकर शरण ले ली और सारे मुस्लिम जो बड़े हैं, वो फर्टिलिटी के कारण नहीं बढ़े हैं, वहां से ढेर सारे मुस्लिम भाई यहां घुसकर आए। अब हमने विभाजन किया, तब तय था कि दोनों देशों में सभी प्रकार के धर्मों के मनाने की छूट रहेगी, भारत में तो वो रहा, आर्टिकल 19 और 21 ने सबको प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित इस्लामिक राष्ट्र बन गए, उनका राज्य का धर्म इस्लाम को बनाया गया और फिर कई बार अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं हुईं,

इसके कारण वहां से हिंदू भागकर भारत की शरण में आया और यह आजादी के वक्त, आजादी के तुरंत बाद भारत के सभी नेताओं ने दिया हुआ वादा था कि अभी यहां आपा धापी में बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, आप अभी मत आइए, जब भी आप आना चाहोगे, आपको हम स्वीकार करेंगे। ये वादा था और एक प्रकार से नेहरू-लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया था। मगर वे जब आए, तो उनको शरणार्थी मान कर इस देश में स्वीकार कर लिया गया, परंतु इनको नागरिकता नहीं दी। कोई 1965 में आया, कोई 1971 में आया, कोई 1981 में आया, कोई 1991 में आया, कोई 2001 में आया, चार-चार पीढ़ी हो गई, उसको नागरिकता नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? कि आप वहां थे, क्यों वहां थे? भारत ने विभाजन को स्वीकार किया, इसलिए वे वहां थे और हमने वादा किया था कि 1951 में वादा किया था, आप जभी भी आओगे हम आपको स्वीकार करेंगे। तो शरणार्थियों की वैधानिक नागरिकता के बगैर बड़ी फौज खड़ी हुई है और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीएए का कानून लेकर हम आए और उनको नागरिकता देने का काम किया। उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मैं बोल-बोलकर थक गया और मीडिया ने भी मेरे साथ अन्याय किया है, इस बात को कभी प्रमुखता से नहीं दोहराया कि सीएए किसी की नागरिकता छीन नहीं सकता, सीएए नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम है। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही नहीं, जो शरणार्थी है, उसको नागरिकता देने का प्रावधान है, तो जो ऐतिहासिक गलती 1951 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेन्द्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से कानूनी दृष्टि से, अवैध रूप से हिंदू शरणार्थी रहते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए, इससे 1951 से लेकर 2014 तक 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी, उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहर लाल नेहरू जी का वादा था कि जब आप आओगे, तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे और हम मुकर गए, पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नही मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था, ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था, धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी का था, देश की संसद का नहीं था और इसके कारण ये लोग चार-चार पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख रुपये तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर और जब यह कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल, अन्याय पूर्ण तरीके से बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है, तो कैसे काम होता है?

आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। 1951 से जो वंचित किया, उसको देने का काम किया है, अब वह कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है? वह भी मैं समझाना चाहता हूं, जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है, तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है, तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिसके लिए, जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वे घुसपैठिए हैं और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दें, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। हर एक को यहां आने की स्वतंत्रता नहीं है, विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां न्याय नहीं हुआ है, वह यहां आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृहमंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है और अगर कोई आर्थिक रूप से कमाने के लिए या अन्य कोई कारणों से यहां आते हैं तो उसको भारत कैसे स्वीकार कर ले, तो मैं भी पजल में था, ढंग से प्रेशर में जवाब भी नहीं दे पाया था, तो एक 18 साल का बच्चा हरियाणा का मेरे घर पर आया, समय लेकर और बाहर आकर खड़ा ही रह गया। मैंने उस को टाइम दिया,

मैंने बोला- यार काहे परेशान करते हो,

बच्चा - भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो?

मैं- सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना, तो बच्चे का है मेरे साथ मत जोड़ना,

बच्चा - साहब आप सबको कहो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देश में प्रवेश कर देंगे,

मैंने कहा- यार ऐसे कैसे हो सकता है?

बच्चा - सब कुछ कि नहीं वह भूमि लेकर आए। वह भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं।

बड़ा सरल रास्ता उसने सुझाया, मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कराकर भेजा। मैंने कहा कि देश ऐसे नहीं चलता है भाई कि नहीं वो अकेले ना आए, बस जो भूमि हमारी चली गई, वो भूमि के साथ सारे आ जाए, हम स्वागत कर देते हैं इनका, बड़ा सरल तरीका बताया, मगर मैं भी जानता हूं यह संभव नहीं जब होगा तब होगा। परंतु अभी शरणार्थी और घुसपैठिया, दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उनको कम से कम यह गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। इसमें किसी ने दखल नहीं देनी चाहिए। इस देश में रहना, जिन्होंने पसंद किया वो सभी मुसलमानों को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा। अगर आप घुसपैठ कर आते हो, अलग-अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठिए का लेवल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वह भारत में ही रहना चाहते हैं, तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते, इसके लिए भी कानून है। पाकिस्तान से किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करें और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर, उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे, तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए और कुछ जगह कैसा हुआ? 2011 में असम में जनगणना हुई, क्योंकि 2011 की जनगणना एक प्रकार से हमारे शासन में नहीं हुई थी, तो सारे लिबरलर्स, जितने भी उदात्त विचार के प्रतिनिधि हैं वह और कांग्रेस हम पर आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि वह कांग्रेस के टाइम के हैं। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6 प्रतिशत हुआ, जो संभव ही नहीं है, अगर घुसपैठ नहीं हुई है, तो यह संभव ही नहीं है और पश्चिम बंगाल के कई सारे

जिलों में यह वृद्धि दर 40 प्रतिशत क्रॉस कर गया, जो कह रहे हैं कि घुसपैठ काल्पनिक चीज है, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप कैसे जस्टिफाई करते हो और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70-70 प्रतिशत है। मैं तो राज्य की एवरेज बता रहा हूं। यही साबित करती है कि घुसपैठ हुई है, होती है। पार्लियामेंट में विशेष कर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की सांसद मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अभी हो रही है या नहीं हो रही? मैंने कहा अभी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है भाई। मगर एक बार देश की सीमा देख कर आओ, सिर्फ बांग्लादेश के सीमा पर कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है, जहां बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है, वहां से घुसपैठ होती है। पकड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, गोलियां भी चलती हैं, परंतु जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, जिस प्रकार की भौगोलिक सीमा है, इसमें यह थोड़ा कठिन है। मगर मैंने बोला, मैं अब आपको पूछना चाहता हूं घुसपैठ कर वो कहां जाता है? तो स्वाभाविक है, पहले जिले में जाता है, तो गांव में कोई भी आदमी आएगा, पटवारी को मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई बताओ पटवारी को मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? एक भी पश्चिम बंगाल के पटवारी ने थाने में फरियाद लिखाई हो, तो मुझे बताओ आप। एक भी पुलिस स्टेशन में फरियाद हुई है तो बताओ।

आधार कौन बनाता है, वो जिले की कलेक्टर ऑफिस बनाती है और आधार के आधार पर सारी चीजें होती है, तो घुसपैठ इस तरह की विकट सीमाओं में अकेला केंद्र नहीं रोक सकता। केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ने बड़ी बाड़ भी लगाई है। मगर ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां बाड़ लगाना ही असंभव है, बाड़ को पानी बहा कर ले जाएगा, इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती, तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है। वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते हैं, आश्रय क्यों देते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है।

मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा, आप भी नहीं बचोगे। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपके जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है कोई इसको? हमारे यहां भी सीमा है, गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी सीमा है, क्यों घुसपैठ नहीं होती है भाई? क्यों नहीं होती है? वहां पर भी बॉर्डर है, वहां पर भी बाड़ लगाई है, वहां पर भी बीएसएफ ही है, ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए और यह शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा, वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं, आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, युगांडा में 70 के दशक में ईदी अमीन का शासन आया था, वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए, क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वहां राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वह धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए यहां आता है, उसको राजनीतिक शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा है, तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से होना चाहिए और ये सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है, ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली, नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। अब यह सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। सामाजिक विवाद भी खड़ा करने का काम हो रहा है।

झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई, इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। अभी-अभी चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, यह कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है। उनका सच और झूठ का दायरा बड़ा सीमित हो गया है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार कहती है वो झूठ है और वो काल्पनिक झूठ का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सच हैं, उनका सच और झूठ का दायरा सीमित हो गया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है 1951 से एसआईआर हो रहे हैं और एसआईआर एक प्रकार से चुनाव आयोग का दायित्व है, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ये जब तक हम मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग कभी काम नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है और फ्री एंड फेयर चुनाव तभी हो सकता है जब हम मतदाता सूची मतदाता की व्याख्या के अनुरूप करें। हमारे लोक प्रतिनिधित्व

कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है, सबसे पहली इस की मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो, तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में, कि इस देश में कोई भी वोट डाल सकता है और दूसरी योग्यता 18 साल का आयु है। अब आप 18 साल का आयु पूछोगे है या नहीं है, तो एसआईआर में पूछना पड़ेगा और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा, वो भी समझते हैं कि यह पूछना पड़ेगा। परंतु वह इसलिए विरोध कर रहे हैं इसके कारण जो वोट कटते हैं, वह वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके कटते हैं। ये चुनाव आयोग का दायित्व है। मतदाता सूची का शुद्धीकरण अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग के प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो तो कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो क्या? इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाल सकते, संवैधानिक मर्यादाओं का हर दृष्टि से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है एसआईआर। फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे और कई क्षेत्रों के अंदर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 11 प्रतिशत घुसपैठी पकड़े गए हैं, ये चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धीकरण का जो कार्यक्रम है मतदाता सूची शुद्धीकरण का एसआईआर, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मतदाता की उम्र 18 साल है या नहीं है, वो उनको पूछना ही पूछना है और मतदाता देश का नागरिक है या नहीं है वह पूछने का अधिकार नहीं? यह दायित्व हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है और यह प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

आज एक घुसपैठ की जो व्याख्या हो रही है उसमे दुनिया में 90 प्रतिशत जियो पॉलिटिकल देश भू-राजनीतिक देश है। उनकी देशों की रचना कोई युद्ध के कारण या कोई नोटिफिकेशन से या कौन युद्ध जीता, इसके आधार पर हुई। भारत एक

मात्र देश ऐसा है, बहुत कम देशों में से सबसे बड़ा देश हमारा एक मात्र ऐसा है, हमारे देश की रचना जिओपॉलिटिकल नेचर से स्वभाव से नहीं हुई है, हम जियोकल्चर देश हैं, भू-सांस्कृतिक देश हैं और अगर इसकी आत्मा को समझना है, तो हमें राज्य की सीमाओं के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। इन को शरण क्यों दी? उनको शरण क्यों दी? जो इस देश का वादा था 1951 में, हम उसका वादा पूरा करने का काम कर रहे हैं। विभाजन जब हुआ मैं अभी भी मानता हूं मन से मानता हूं, मेरे कई साथी मेरा विरोध कर रहे हैं, मगर फिर भी मानता हूं, कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की दो भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल किया है, ये कभी नहीं होना चाहिए था। हमारे यहां तो अनेक प्रकार के धर्म सदियों से चल रहे हैं, जैन धर्म कई हजारों साल से चल रहा है, बौद्ध धर्म कई हजारों साल से चल रहा है, दशम पिता ने सिख धर्म की स्थापना की, कई सदियों से हम दसम पिता का भी सम्मान करते हैं। इस देश में कभी धर्म के आधार पर विवाद नहीं हुआ, धर्म के आधार पर देश का राष्ट्रीयता का निर्णय कैसे हो सकता है? धर्म और राष्ट्रीयता दोनों को अलग करना चाहिए था। मगर धर्म और राष्ट्रीयता को अलग नहीं किया, इसके कारण ये सारे बिखराव और विवाद खड़े हुए हैं। अगर नेहरू-लियाकत समझौते का 1951 में ही पालन हो गया होता, तो आज शरणार्थी और घुसपैठियों का यह जो विवाद है, वह विवाद नहीं होता। जब घुसपैठिए मतदाता सूची में होते हैं, तो वह हमारे देश की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार होते हैं। मैं देश के सभी नागरिकों से पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वह तय करने का अधिकार देश के नागरिक के अलावा किसी को मिलना चाहिए क्या, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अधिकार? देश के नागरिकों के अलावा किसी को मिलना चाहिए क्या, तो किस की वकालत कर रहे हैं? देश की जनता ने उनको पूछना चाहिए। जब आप घुसपैठिए को बचाने का काम कर रहे हो, हमारे लोकतंत्र को, हमारे पवित्र संविधान की स्पिरिट को दूषित कर रहे हो। क्योंकि चुनाव ही तो जो है जो लोकतंत्र में देश कौन चलाएगा, उसका फैसला करता है और चुनाव की प्रक्रिया में जो देश का नागरिक नहीं है, उस को मताधिकार देते हो, तब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं बनता है। मुझे कौन इस देश में रहने देगा वो कारण से वोट की जाती है और जब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं रहता है, लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इन तीन सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चली है। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वह डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं, देश की जनता को ''तीन डी'' के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि ये ''तीन डी'' देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इस देश में भी कई करोड़ मुसलमान रहते हैं, कई करोड़ क्रिश्चियन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई रहते हैं, किसी पर किसी ने कुछ आरोप नहीं लगाया। वो भी वोट देते हैं चुनाव प्रक्रिया में, उनका स्वागत है, जो मत है उसका स्वागत है। इस देश में बहुमत में हिंदू समाज रहता है, उसने सालों तक हमें सत्ता पर नहीं आने दिया। ठीक है सत्ता पर से निकाला भी है। कई राज्यों में भी हम चुनाव हारे हैं, अटल जी के छह साल की सरकार के बाद भी हम चुनाव हारे थे, परिणाम जो आए वो आए, परंतु मत देने का अधिकार उसी को होना चाहिए, जो इस देश का नागरिक है, इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा और इस देश के लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई निष्ठा रखे। और यह मूल दायित्व हमारे संविधान ने दिया है, अनुच्छेद 326 में वयस्क मतदाता को ही अधिकार दिया है।

18 साल का और जो हमारा 1950 और 1951 में अमेंडमेंट के साथ जन प्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसमें मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों की पात्रता और मतदाता की पात्रता, यह इसका सटीक जांच करने का अधिकार हमारे चुनाव आयोग को दिया है और एसआईआर पहली बार नही हो रही। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी जी को तो मालूम ना हो, मगर अभी भी कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बचे हैं, उनको तो कहना चाहिए कि आपके नाना ने भी कराया था, आपकी दादी ने भी कराया था, आपके पिता ने भी कराया था, काहे को विरोध कर रह हो? वह बोलते ही नहीं है हमने कराया था। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं, कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम, ये पवित्र काम है हमारे लोकतंत्र को शुद्धि देगा।

फिर से मैं कहना चाहता हूं घुसपैठिए की इतनी बड़ी संख्या किसी देश को सुरक्षित नहीं रखती, सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीति और कानून और व्यवस्था दोनों को वह प्रभावित कर रही है, शहरी क्षेत्रों में भी भारत के गरीब मजदूरों के अधिकार को वह छीनते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक आक्रमण के साथ-साथ जमीन पर कब्जा करने का भी अभियान चला है और यह किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इसीलिए इस 15 अगस्त को नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से हाईपावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने की घोषणा की है, वो मिशन अनेक प्रकार के काम करेंगे। अवैध प्रवासन मतलब घुसपैठियों की जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन, भी वो डेमोग्राफिक मिशन करेगा, धार्मिक और सामाजिक जीवन पर जो असर पड़ रहे हैं इसका भी अभ्यास करेगा। जनसांख्यिकी के बदलाव के संभावित कारणों का भी अध्ययन करेगा, असामान्य बसावट की पैटर्न और दीर्घकालीन प्रभाव जो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं इसका भी अध्ययन करेगा और सीमा प्रबंधन पर जो बोझ आता है इसका भी ये अध्ययन करके, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे।

मुझे मालूम है यह रिपोर्ट आते ही फिर से एक बार बड़ा विवाद होने वाला है। मगर विवादों और देश की सुरक्षा, विवाद और हमारे देश की संस्कृति को बचाना, विवाद और हमारे लोकतंत्र को बचाना, ये दोनों में से अगर किसी को चयन करना है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने को, संस्कृति बचाने को चयनित करती है और दृढ़ता के साथ जो विवाद खड़े होते हैं, इसका हम जवाब देश की जनता के सामने देंगे और देश की जनता से भी करबद्ध निवेदन है प्रचार में आए बगैर, तथ्यों की गहराई में जाइए, तथ्यों में गोता लगाकर सत्य को ढूंढ लीजिए। जब तक हम हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं, विश्व में हमें कोई नहीं बचा सकता, देश के नागरिकों के अधिकार बचाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। पड़ोस के देश से जो रिलीजियस प्रताड़ना के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आते हैं वो घुसपैठिए नहीं हैं, वो शरणार्थी हैं। शरणार्थियों का भारत में स्वागत है। उनको नागरिकता भी मिलेगी, अब कानून बन चुका है और घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये तीन ही रास्ते बचे हैं। ▪

मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनेगा- अमित शाह

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉनक्लेव की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवेश संबंधी कार्यों की शुरुआत हुई है, जो अन्य राज्यों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। जो 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है, वह देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन किसी एक क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

- **महान वक्ता, संवेदनशील कवि, लोककल्याण को समर्पित नेता और आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नींव रखने वाले श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ।**
- **राज्य के विकास के लिए मोदी जी द्वारा स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल समिट की शुरुआत की गई, उसी दिशा में राज्य के समविकास के लिए मोहन यादव जी ने क्षेत्रीय इनवेस्टमेंट समिट की परंपरा शुरू की।**
- **आने वाले समय में ऐसे क्षेत्रीय इनवेस्टमेंट समिट राज्यों के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।**

देश में स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव्स की शुरुआत गुजरात से हुई, जब श्री नरेन्द्र मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे। Vibrant Gujarat के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की वैज्ञानिक शुरुआत मोदी जी ने की, जो काफी सफल हुआ और उससे गुजरात में निवेश भी आया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉनक्लेव की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवेश संबंधी कार्यों की शुरुआत हुई है, जो अन्य राज्यों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। जो 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है, वह देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन किसी एक क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी क्षेत्र की जनता के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि राज्य का संतुलित विकास नहीं होता, तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में अपार संभावनाएँ छिपी होती हैं। मालवा और चम्बल क्षेत्रों में कपास किसानों का बहुत पुराना उत्पाद रहा है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण कपास की खेती बहुत कम हो गई। अब पीएम मित्र पार्क के माध्यम से फिर से कपास मुनाफे की फसल बन गई है।

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भौगोलिक स्थिति है। आधे भारत को यहाँ से बहुत कम परिवहन लागत से सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसका शत-प्रतिशत दोहन तभी हो सकता है जब मध्य प्रदेश में उद्योग symmetrically लगें। दक्षिणी राज्यों से सटे जिलों में, दिल्ली से सटे क्षेत्रों, जैसे ग्वालियर, में उद्योग लगे, पश्चिम से सटे क्षेत्रों, जैसे धार और झाबुआ में भी उद्योग लगे, तभी भौगोलिक स्थिति का लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय निवेश समिट ने राज्य के चहुँमुखी विकास की नींव डालने का काम किया है।

ग्वालियर से जुड़े 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ। एक जमाने में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बनकर रह गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश से बीमारू का टैग हटाया और अब मोहन यादव जी नई ऊर्जा के साथ राज्य के विकास का काम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर विकसित राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश में शानदार राजमार्ग बन चुके हैं, माँ नर्मदा का पानी अधिक से अधिक क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया गया है, सिंचाई के रकबे में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है, और पंजाब एवं हरियाणा को पीछे छोड़ कर मध्य प्रदेश ने लगातार सात बार 'कृषि कर्मण' अवार्ड जीतने में सफलता प्राप्त की है।

मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए इंदौर में एक मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, जो

उत्पादन में लगी देश भर की कंपनियों को अपना गोदाम या हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक समय मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा है। मेट्रो के परिचलन में सबसे कम लागत मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी राज्य ने अच्छा काम किया है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मिनरल, मिनरल आधारित उद्योग, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, पर्यटन सहित हर क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी है और स्टार्टअप भी बना है। इनमें लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। मध्य प्रदेश ने सिर्फ एक साल में 4 लाख 57 हजार नई MSME इकाईयां स्थापित करने का रिकार्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में हब बनने जा रहा है और स्टार्टअप एवं इनोवेशन से इसे नई ऊंचाई मिलने वाली है।

पीएम मित्र पार्क 5F के विजन से बना है, जो किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने का भी काम करता है। इसमें Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign शामिल है, यानि पीएम मित्र पार्क में एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था है। सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में है, जिससे किसानों को फायदा होगा। टेक्सटाइल और पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, और इन दोनों क्षेत्रों के अनुकूल संरचना मध्य प्रदेश में बन रही है। Ease of Doing Business में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है।

मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) 700 बिलियन डॉलर के रिकार्ड स्तर को पार कर गया है। हमने सेमी-कंडक्टर इंडस्ट्री में देर से ही सही, लेकिन धमाकेदार एंट्री की है और हम देखते ही देखते इस क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि इसके निर्यात की भी शुरुआत करेंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकास किया है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सिर्फ सात करोड़ थी, जो सितंबर 2025 में बढ़कर 101 करोड़ हो गई है। अब ब्रॉड्बैन्ड यूजर्स की संख्या भी लगभग 99 करोड़ हो गई है। देश के 95 प्रतिशत हिस्से में 4जी कनेक्टिविटी है और अब 99 प्रतिशत हिस्से में 5जी कनेक्टिविटी पहुंचाने की तैयारी है। UPI के माध्यम से Digital Transaction और FinTech के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2024-25 में करीब 50 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन भारत में हुए हैं। अगस्त 2025 में 25 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 करोड़ Digital Transaction करके हमने दुनिया को पीछे छोड़ा है। कोरोना से मुकाबले के दौरान वैक्सीन बनाने और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60 प्रतिशत वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है, भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है। रक्षा निर्यात और रक्षा विनिर्माण को भी रीस्ट्रक्चर किया गया है। Ease of Doing Business में भारत 2014 में 142 वें स्थान पर था, आज 63 वें स्थान पर हैं। Insolvency and Bankruptcy Code ने एक स्ट्रक्चर्ड आर्थिक व्यवस्था बनाई है।

मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के प्रयास किए हैं। पिछली सरकार के समय में 90 हजार किलोमीटर राजमार्ग थे, अब 1 लाख 50 हजार किलोमीटर लंबे राजमार्ग नए बने हैं। फोर लेन हाइवे पहले 18000 किलोमीटर थे, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क पहले 3 लाख 81 हजार किलोमीटर थी, अब 7 लाख 84 हजार किलोमीटर बनी। पहले 74 हवाई अड्डे थे, अब इनकी संख्या 163 है। पहले एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, अब 164 वंदे भारत ट्रेन बन रही है और वंदे भारत ट्रेन के कल पुर्जे बनने की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई है। पहले एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, अब 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22 हजार किलोमीटर था, अब 68 हजार किलोमीटर है। मेट्रो कनेक्टेड शहर पहले पाँच थे, अब इनकी संख्या 23 है। पहले सिर्फ 100 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था, अब 2 लाख 14 हजार पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुँच चुका है।

मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इतनी आकर्षक है कि हर जगह बीज बो कर फसल प्राप्त की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमि इतनी उर्वर है कि यहाँ रुपया बो कर करोड़ों कमा सकते हैं। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है, तब इसका सबसे अधिक फायदा राज्य की जनता और उद्योग जगत को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री सस्टेन करती है और सफल होती है।

पूरा देश एक युग पुरुष, एक स्वप्न द्रष्टा और आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव डालने वाले अटल जी की जयंती मना रहा है। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम इस मिट्टी ने किया। अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत बचाने में मदद की, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के 'स्व को जगाने और स्वराज से सुशासन तक की यात्रा को आगे ले जाने का काम किया।

जब अंग्रेजी का बोलबाला हुआ करता था, तब अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी में भाषण देकर हर भारतवासी का दिल जीतने का काम किया। पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले केन्द्र में आदिवासियों के लिए कोई अलग विभाग नहीं था, लेकिन उनके शासन काल में भारत सरकार में जनजातीय विभाग की स्थापना हुई और ट्राइबल कल्याण की नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से चुनाव नहीं जीते जाते की दकियानूसी सोच को खत्म कर अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लागू की, जिसके तहत देश को हर तरफ से जोड़ने वाले छह राजमार्ग का निर्माण कर देश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया।

अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने यह सिद्धांत प्रस्थापित किया कि शांति के लिए भी परमाणु शक्ति संपन्न बना जा सकता है। उन्होंने दुनिया भर के विरोध के बावजूद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, तब दुनिया भर का दबाव था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से बातचीत करे, लेकिन अटल जी ने दृढ़ता से कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है, अब पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं हो सकती, जब तक भारत से एक-एक घुसपैठिया खदेड़ न दिया जाए। कारगिल में विजय अटल जी के दृढ़-निश्चयी नेतृत्व का परिचायक है। अटल जी एक महान वक्ता, संवेदनशील कवि और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। उन्हें पूरा जीवन अजात शत्रु माना गया, जबकि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। अटल जी के खिलाफ उनके विरोधी भी कुछ नहीं बोलते थे।

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर गांधीजी के सहयोगी के रूप में और फिर हिन्दू महासभा के सृजन और हिन्दू विचार को जो इस देश का मूल विचार है, उसे बिना किसी संकोच के देश में प्रस्थापित करने का काम किया। आगे चलकर वही बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने अनेक नेता देश को दिए, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। ▪

निवेश, रोजगार और समावेशी विकास का नया मॉडल मध्य प्रदेश -डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश निवेश, रोजगार और समावेशी विकास का एक नया मॉडल गढ़ रहा है। अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट से प्रदेश में औद्योगिक विस्तार को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्यप्रदेश अब साकार होती संभावनाओं का अग्रणी केंद्र बन चुका है।

मध्यप्रदेश में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है। मध्यप्रदेश, देश का दिल होने के साथ-साथ देश की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख पड़ाव है। मध्यप्रदेश अनंत संभावनाएं लिए हुए है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश व्यापार, व्यवसाय, उद्योग-धंधे लगाने से लेकर अपने उत्पाद को निर्यात करने के लिए एक अनुपम केंद्र बन रहा है। मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां प्राकृतिक संसाधन, उद्योग-अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिर शासन सभी निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण तैयार करते हैं।

मध्यप्रदेश अपनी कई विशिष्ट पहचानों के कारण पूरे देश में अद्वितीय है। प्रदेश में 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, आईटी और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में स्थापित हो रहा है। मध्यप्रदेश राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। निवेशक भारत के दिल से जुड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश भी हमेशा निवेशकों के साथ सहयोग और साझेदारी करने में पीछे नहीं रहेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। श्रद्धेय अटल जी राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष एवं राजनीति के अजातशत्रु थे। मध्यप्रदेश में गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश इसी 11 दिसंबर को नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये हर संभव कोशिश कर रही है। मध्यप्रदेश में 8.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं। अटलजी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के साथ-साथ ग्वालियर को भी बड़ी सौगातें मिल रही हैं। ▪

अटल जी भारत की आत्मा की आवाज थे -हेमंत खण्डेलवाल

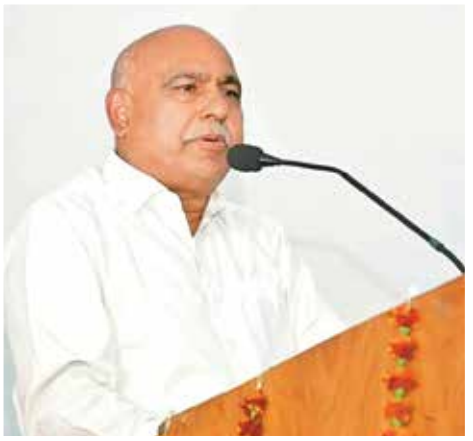

भारत रत्न, राष्ट्रनायक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनके गृहनगर ग्वालियर में आयोजित भव्य समिट में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास एवं औद्योगिक कार्यों का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। श्रद्धेय अटल जी की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को निवेश के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश देश में तीसरा सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाला राज्य बना है। धार में स्थापित पीएम मित्र पार्क, निवेशकों को सुविधाजनक वातावरण देने हेतु डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों की नीतियों में सुधार, 18 नई औद्योगिक नीतियाँ, सरल एवं पारदर्शी निवेश प्रणाली तथा अब तक प्राप्त 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सभी मिलकर नए मध्यप्रदेश की विकास गाथा रच रहे हैं। यह युवाओं के रोजगार, किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रदेश की आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन और उपस्थिति से श्रद्धेय अटल जी की जयंती का कार्यक्रम ऐतिहासिक बन गया है। अटल जी के सपनों का भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का भारत आज एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। सभी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों एवं राष्ट्र प्रथम, सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा और गरीब कल्याण को अपने जीवन और कार्य में उतारने की आवश्यकता है। ▪

अब, भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर - पीएम मोदी

Transforming Tomorrow की चर्चा से देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro- economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रजीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के

अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है।

विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं।

भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, गांव, टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज, नारी-शक्ति, इनोवेटिव यूथ पावर, सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ FPO's तो ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

भारत की नारी-शक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready4 विक्रम-वन बना रही है।

सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

भारत में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

रिफॉर्म के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्यौहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को तबाह कर दिया, और हम इसको रिवाइव कर रहे हैं। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आजादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया। गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाजों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां जरा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है। पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई

गीत नहीं गाता हूँ

अटल बिहारी वाजपेयी

बेनकाब चेहरे हैं,
दाग बड़े गहरे हैं,
टूटता तिलस्म,
आज सच से भय खाता हूँ।
गीत नहीं गाता हूँ।

लगी कुछ ऐसी नजर,
बिखरा शीशे सा शहर,
अपनों के मेले में
मीत नहीं पाता हूँ।
गीत नहीं गाता हूँ।

पीठ में छुरी सा चाँद,
राहु गया रेखा फाँद,
मुक्ति के क्षणों में
बार-बार बँध जाता हूँ।
गीत नहीं गाता हूँ।

मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा। ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी। पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हजार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। ये जो मैंने आंकडे दिए हैं, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी जरूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग जीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे। ▪

गांव-गांव पहुंच रहा है इलाज- जगत प्रकाश नड्डा

- **पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज से बदलेगी बैतूल की तकदीर, गांव-गांव पहुंचेगा इलाज।**
- **मध्यप्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, हजारों करोड़ का निवेश।**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।**
- **एम्स और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, 2029 तक 75 हजार नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी।**
- **मध्यप्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार,14 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे।**
- **तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में चौथे स्थान पर भारत।**

पीपीपी मोड पर बैतूल में बनने वाला मेडिकल कॉलेज क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा। इससे भविष्य में प्रदेश के गांव-गांव तक डॉक्टर और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही बैतूल को स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाना सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल बीमारों का इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारियों की रोकथाम करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकेंद्रीकरण हुआ है। आज देशभर में 1 लाख 81 हजार से अधिक आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार जच्चा-बच्चा की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और आज देश मीजल्स, रुबेला एवं कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) जैसी बीमारियों से मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका है।

देश में नवजात बच्चों को 12 प्रकार के जीवनरक्षक टीकाकरणों के 27 डोज दिए जा रहे हैं। शून्य से 16 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र

सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण में अग्रसर है। देशवासियों की डेंटल और मानसिक स्वास्थ्य की भी खास देखभाल की जा रही है। वर्तमान में देश भर में 30 लाख लोगों ने टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत देश की 140 करोड़ आबादी में से 62 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर जाति, धर्म और वर्ग के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित कर रही है। पहले नागरिकों की जेब से स्वास्थ्य पर 70 पैसे खर्च होते थे, जो अब केवल 30 पैसे रह गए हैं। देशभर में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वर्ष 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 819 हो चुके हैं। धार और बैतूल में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को जोड़ने के बाद देश में कुल 821 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वर्तमान में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 1 लाख 29 हजार एमबीबीएस सीटें हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2029 तक एमबीबीएस की 75 हजार नई सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

मध्यप्रदेश के रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान की गई है। उज्जैन मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के दतिया, खंडवा, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में 14 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश में कभी केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 33 हो चुके हैं, और भविष्य में प्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। संचालित मेडिकल कॉलेजों में 850 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में 850 पीजी सीटों के विस्तार के लिए 702 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को 1804 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 15 वें वित्त आयोग में भी प्रदेश को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद मिला है। प्रदेश के धार और बैतूल में दो मेडिकल कॉलेजों का भूमि-पूजन संपन्न हुआ है, और नए साल के जनवरी माह में कटनी और पन्ना में दो नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि-पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते हुए विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और जल्द ही तीसरे स्थान पर भी पहुंचने की संभावना है। आज विश्व में 93 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के वैश्विक आंकड़ों में 50 प्रतिशत अकेले भारत में यूपीआई के माध्यम से किए जा रहे हैं, और भारतीय यूपीआई वर्तमान में 9 देशों में संचालित हो रही है। विश्व की बड़ी संस्थाओं के अनुसार, दुनिया में मंदी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।

मध्यप्रदेश के लिए रेल बजट 9 गुना बढ़ाया गया है, और प्रदेश में अमृत स्टेशन और मेट्रो जैसी सुविधाओं की सौगात दी जा रही है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लांट लग रहा है, जिसकी क्षमता 750 मेगावॉट होगी। जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विकास कार्य भी संपन्न हुआ है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। ▪

परियोजनाओं व विकास कार्यों की मिलेगी सौगात-डॉ. मोहन यादव

- **जनजातीय समुदाय के वीरों, महापुरूषों ने निडरता से देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।**
- **प्रदेश सरकार ने दो वर्षों में स्वास्थ्य व औद्योगिक विकास के साथ सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किए।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस वर्ष फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का शुभारंभ कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष अब तक 8.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आया है, जिसमें से 6.5 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए 25 दिसंबर को उनकी जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दो लाख करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन व लोकार्पण मध्यप्रदेश की धरती ग्वालियर में किया। यह सौगातें मध्यप्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्ष में औद्योगिक विकास के साथ सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं निरंतर बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कर कमलों से देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि-पूजन किया गया है। इससे मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इसी तरह राज्य सरकार ने पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना (पीकेसी) के माध्यम से सालों से लंबित विवाद को सुलझाया है। इससे राजस्थान और उत्तरी मध्यप्रदेश और मालवांचल को सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र के साथ मिलकर ताप्ती मैया के लिए भी 70 हजार करोड़ की बड़ी योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार ने जनजातीय नायकों के नाम पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक कर उन्हें सम्मान देने का कार्य किया है। इसके साथ ही जनजातीय समाज की समृद्ध व गौरवशाली विरासत को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय का देश को आजाद कराने में बहुत अहम योगदान है। आजादी के बाद की सरकारों ने जनजातीय समुदाय के योगदान को जनता तक नहीं पहुंचाया। एक सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले श्रद्धेय अटल जी ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। उन्होंने गांव-गांव सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। बैतूल में गुड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा। कढ़ाई वुडन कलस्टर से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी वृहद स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। माही उद्योग क्षेत्र मुलताई में इंडस्ट्रीयल कलस्टर और कोषमी औद्योगिक ईकाई द्वितीय चरण बनेगा। ▪

विकास की संभावना वाले सभी उद्योग खुलेंगे- हेमंत खण्डेलवाल

- **आजादी के बाद बैतूल विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी छलांग लगाई है।**
- **मेडिकल कॉलेज की सौगात से बैतूल के विकास का नया युग प्रारंभ हो रहा है।**
- **बैतूल में सभी खेलों के राष्ट्रीय स्तर के मैदान तैयार किए जाएंगे।**

बैतूल के लोगों को गंभीर बीमारी होने पर भोपाल और नागपुर इलाज कराने जाना पड़ता है। जनजातीय बाहुल्य जिला होने के कारण यहां अधिकांश लोग गरीब परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन कर जिले को बहुत बड़ी सौगात दी है। 600 बिस्तरों वाला मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जिले में एक हजार बेड उपलब्ध हो जाएंगे। वर्तमान में चिकित्सा सुविधा सबसे बड़ी जरूरत है। 75 प्रतिशत बिस्तरों पर गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। बैतूल जिला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जिले में अनेकों प्रकार के पशु-पक्षी हैं। मध्यप्रदेश को पहली ताप्ती फॉरेस्ट रिजर्व की भी सौगात मिलने जा रही है।

बैतूल खेलों के हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेल प्रतिभाओं का आगे बढ़ाने को सभी तरह के खेलों के राष्ट्रीय स्तर के मैदान और सुविधाएं जिले में उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बैतूल में कई तरह के उद्योग अभी संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। बैतूल में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। आने वाले दिनों में बैतूल में वह सभी उद्योग खोले जाएंगे, जो यहां तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ▪

डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जारी रहेगा- अमित शाह

विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 324 से ही चुनाव आयोग की रचना हुई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भीतर चुनाव आयोग का गठन, उसकी संरचना, कार्य और शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा, मतदाता सूची के निर्माण और उसके सुधार से जुड़ी शक्तियों के बारे में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे।

मतदाता सूची तैयार करने और उसमें सुधार करने का दायित्व भी चुनाव आयोग को दिया गया था। अनुच्छेद 325 यह प्रावधान करता था कि किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता था। अनुच्छेद 326 मतदाता की पात्रता के गहन निरीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। इसमें मतदाता की योग्यता और मतदाता बनने की शर्तें तय की गई थीं। पहली शर्त यह निर्धारित की गई थी कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए और विदेशी नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर स्पष्ट किया गया था कि चुनाव आयोग यह प्रक्रिया इसलिए संचालित कर रहा था क्योंकि यह उसका संवैधानिक दायित्व था। दूसरी शर्त के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता था। तीसरी शर्त के रूप में वैधता का निर्धारण किया गया था, जिसमें मानसिक असमर्थता, अपराध या भ्रष्टाचार में संलिप्तता जैसे मामलों पर समय-समय पर कानून द्वारा तय मापदंड लागू होते थे। इन्हीं तीन आधारों पर भारत के मतदाता होने की पात्रता तय की जाती थी और इन सभी बातों की जांच का दायित्व चुनाव आयुक्तों, अर्थात् चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स को सौंपा गया था। अनुच्छेद 327 के अंतर्गत मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन तथा इससे संबंधित कानून बनाने की सिफारिश करने की शक्ति भी चुनाव आयोग को प्रदान की गई थी।

हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई थी। सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण 1952 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इसके बाद 1957 में पुनर्निरीक्षण हुआ था, तब भी नेहरू ही प्रधानमंत्री

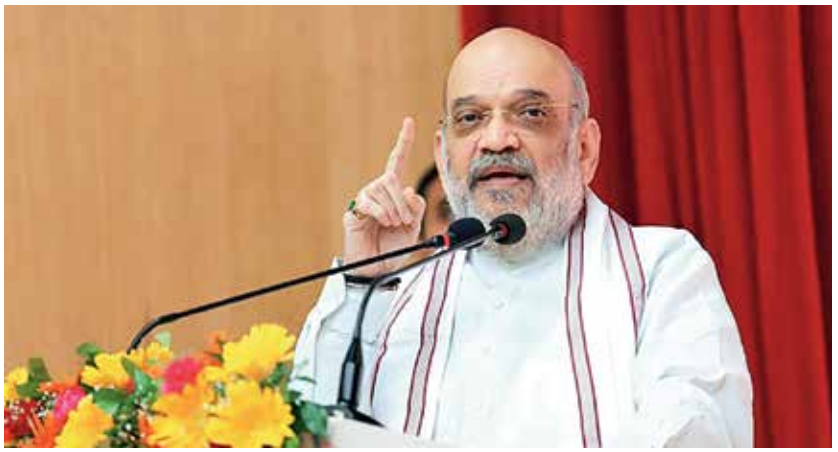

थे। 1961 में तीसरा पुनर्निरीक्षण हुआ था और उस समय भी प्रधानमंत्री नेहरू थे तथा कांग्रेस ही सत्ता में थी। 1965-66 में दो वर्षों में एक बार फिर पुनर्निरीक्षण हुआ था, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वे भी कांग्रेस से थे। 1983-84 में पुनर्निरीक्षण हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, 1987-89 में राजीव गांधी के समय विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया गया था, 1992-93-95 के दौरान नरसिम्हा राव के समय यह प्रक्रिया चली थी, और 2002-03 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह हुआ था। 2004 में यह प्रक्रिया समाप्त हुई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार कुल 23-24 गहन पुनर्निरीक्षण हुए थे, जिनमें दो वर्ष एनडीए की सरकार और एक वर्ष मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुआ था। 2004 के बाद 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा था और इस समय वर्तमान सरकार थी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि 2004 तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया का विरोध नहीं किया था, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को पवित्र और लोकतंत्र को स्वस्थ रखने का माध्यम माना गया था। यदि लोकतंत्र में चुनाव मतदाता सूची पर आधारित थे और वही सूची प्रदूषित होती, तो चुनाव साफ-सुथरे नहीं हो सकते थे। इसलिए समय-समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण आवश्यक माना गया था और इसी कारण चुनाव आयोग ने 2025 में इसे आयोजित करने का निर्णय लिया था।

देश का लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता था जब यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चयन घुसपैठियों द्वारा न हो। इस प्रक्रिया से कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ प्रभावित होते थे, क्योंकि ऐसे दलों को देश के मतदाताओं से तो वोट नहीं मिलता था, विदेशी नागरिकों से मिलने की आशा भी अब समाप्त हो रही है। राष्ट्रहित में यह निर्णय करना आवश्यक था कि क्या इस देश की संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनने के लिए विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए या नहीं।

विपक्षी नेता मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, चाहे वह पुरानी हो या नई। लेकिन मतदाता सूची से चुनाव परिणाम नहीं तय होते और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के कार्यों को समर्पित रहती है।

2014 के बाद भी भाजपा ने कई चुनाव हारे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कुछ हार हुई, तेलंगाना और बंगाल में जीत नहीं मिली, चेन्नई में भी सफलता नहीं मिली। जब भाजपा हारती थी तब विपक्ष मतदाता सूची को दोषी नहीं ठहराता था, जबकि विपक्ष की जीत के समय वही सूची उत्कृष्ट मानी जाती थी। यह दोहरे मानक का उदाहरण था। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। जब कोई जीतता है तो चुनाव आयोग महान दिखाया जाता है और हारने पर वह निकम्मा बताया जाता है। यह भ्रांति फैलाने का प्रयास था और उनका दायित्व है कि देश की जनता को इस ड्यूल स्टैन्डर्ड के विषय में सटीक जानकारी दें।

पहली वोट चोरी तब मानी जाती है जब किसी

व्यक्ति के पास मतदाता होने की योग्यता न हो और फिर भी वह वोट डाल दे। दूसरी चोरी तब होती है जब कोई गलत तरीके से चुनाव जीत ले। तीसरी चोरी तब कहलाती है जब कोई व्यक्ति जनादेश के विपरीत जाकर कोई पद हासिल कर ले, यह भी वोट चोरी का ही एक रूप है। पहली बड़ी घटना आजादी के बाद हुई, जब देश के प्रधानमंत्री का चयन होना था। कांग्रेस के प्रांतीय समितियों के चुनाव में 18 वोट सरदार वल्लभभाई पटेल को मिले थे और केवल दो वोट जवाहरलाल नेहरू को। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यह जनादेश की पहली अनदेखी थी। दूसरा उदाहरण नैतिक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई थीं, लेकिन श्री राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि श्रीमती गांधी ने चुनाव उचित तरीके से नहीं जीता है। इसके बाद हुई सबसे बड़ी चोरी यह थी कि इंदिरा गांधी ने इस निर्णय को ढकने के लिए संसद में कानून लाकर अपने विरुद्ध चल रहे केस पर रोक लगवा दी यानी स्वयं को ही इम्युनिटी दे दी। चुनाव आयोग की इम्युनिटी पर प्रश्न उठाने वाले विपक्ष के नेता इस ऐतिहासिक इम्युनिटी पर क्या कहते हैं, जो स्वयं श्रीमती गांधी ने अपने लिए बनाई थी। श्रीमती गांधी ने तो स्वयं के लिए इम्युनिटी ली थी और यही नहीं, जब संवैधानिक सुधारों पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई, तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जजों को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और उसी व्यवस्था से निर्णय सुनिश्चित करवाया गया। यह सब इतिहास में दर्ज है, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है और इसे कोई झुठला नहीं सकता।

तीसरे प्रकार की वोट चोरी - जब किसी व्यक्ति की योग्यता नहीं होने के बावजूद वह मतदाता बन जाता है। हाल ही में दिल्ली की सिविल अदालत में एक विवाद दर्ज हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी के मतदाता बनने से पहले की स्थिति को लेकर केस चल रहा है।

लोकतंत्र की प्रक्रिया में सभी की साझेदारी रही है। भाजपा भी लंबे समय तक विपक्ष में बैठी और जितना चुनाव जीते, उससे अधिक हारे। उनकी राजनीतिक जीवन की एक बड़ी अवधि विपक्ष में बीती, चाहे राज्य की राजनीति हो या केंद्र की। इसके बावजूद उन्होंने कभी चुनाव आयुक्तों या चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया। अब एक नया पैटर्न और एक नया पेटेंट दिखाई देने लगा है। पहले ऐसी परंपरा केवल कांग्रेस में दिखाई देती थी, मगर अब संपर्क के दायरे में आने वाले अनेक दल भी यही कर रहे हैं और इंडी एलायंस के नेता लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप दोहरा रहे हैं। चुनाव आयोग एक तटस्थ और संवैधानिक संस्थान है, जिसकी मान्यता किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि संविधान ने दी है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर बार-बार सवाल उठाकर और आरोप लगाकर विपक्ष पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार की छवि धूमिल करने से उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तव में वे देश की लोकतांत्रिक साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मतदाता तो जानता है कि उसने किसे वोट दिया और उसी विश्वास से प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, इसलिए मतदाता के मन में कोई संदेह नहीं है। विपक्ष लगातार ''वोट चोरी के आरोप लगाता रहा'', घुसपैठिया बचाओ यात्राएँ निकालता रहा, जबकि बिहार में भाजपा दो-तिहाई बहुमत से जीती। एक नई परंपरा शुरू हो गई है, चुनाव न जीतो तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसी चुनाव आयोग के रहते विपक्ष अनेक चुनाव जीत चुका है, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर आज वही दल आयोग पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं।

मई 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय से विपक्ष को आपत्ति शुरू हुई। इसके बावजूद एनडीए ने लगातार जीत दर्ज की। तीन लोकसभा चुनाव जीते, इकतालीस राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, कुल मिलाकर 44 विधानसभा चुनावों में विजय मिली और 2024 से 2025 के बीच भी लगभग 30 चुनाव अलग-अलग राज्यों में जीते गए। यदि विपक्ष को वास्तव में मतदाता सूची पर भरोसा नहीं है, तो फिर उन्होंने शपथ क्यों ली, चुनाव क्यों लड़ा और यहां तक पहुंचे कैसे? राहुल गांधी जिस वायनाड से चुने गए थे, वहां की मतदाता सूची को लेकर भी भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्य प्रस्तुत किए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेठी के मामले में भी यही स्थिति रही। मतदाता सूचियों की हल्की-फुल्की त्रुटियों को विपक्ष चुनाव हारने का कारण बताता है, जबकि चुनाव हारने का वास्तविक कारण कुछ और है। यदि विपक्ष सच में मानता है कि मतदाता सूची सही नहीं है, तो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण ही उसका समाधान है। लेकिन उसी प्रक्रिया में विपक्ष सहयोग नहीं करता, बीएलओ को सहयोग नहीं मिलता, कई विपक्षी राज्य सरकारें मदद नहीं करतीं और फिर वही दल मतदाता सूची के शुद्धिकरण की मांग भी करते हैं। चुनाव आयोग उनकी ही मांग पूरी कर रहा है, फिर भी वे उस पर आरोप लगाते हैं। आज स्थिति यह है कि यदि प्रेस में कोई पत्रकार विपक्ष के नेताओं को पसंद न आने वाला सवाल पूछ दे, तो वे उसे ''भाजपा का एजेंट'' कह देते हैं। जबकि पत्रकार लोकतंत्र का स्तंभ होता है, उसका किसी दल से लेना-देना नहीं होता। लोकतंत्र में केवल मनपसंद सवालों की अपेक्षा इमरजेंसी की मानसिकता है और वर्तमान समय इमरजेंसी का नहीं है। जब केस अदालत में चलते हैं, तो विपक्ष जजों पर आरोप लगा देता है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जब ईवीएम वाला तर्क नहीं चलता तो ''वोट चोरी का मुद्दा'' उठाकर पूरे बिहार में यात्राएँ निकालते हैं और फिर भी हार जाते हैं। हारने का कारण न ईवीएम है, न मतदाता सूची, हारने का असली कारण उनका नेतृत्व है। यदि विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा, तो यह उनकी भूल है। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपने नेतृत्व से सवाल पूछेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने चुनाव कैसे हार गए।

ईवीएम को कानूनी रूप से 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होने के समय लाया गया। अब उसी ईवीएम के कानून का विरोध किया जा रहा है। इसके बाद ईवीएम के खिलाफ याचिकाएँ दायर हुईं और सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों ने 2002 में इसे कानूनी मान्यता दी। इसके बावजूद विपक्ष न तो राजीव गांधी को मानता है और न ही सर्वोच्च अदालत को। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का परीक्षण किया गया, ताकि चुनाव की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित और पारदर्शी है, यह सुनिश्चित किया जा सके। ईवीएम का पूरा देश में पहला प्रयोग 2004 के लोकसभा चुनाव में हुआ और 2009 के चुनाव में भी पूरी तरह ईवीएम का उपयोग हुआ। जब 2014 में भाजपा जीत रही थी, तब ईवीएम का कानून लागू किया गया और विपक्ष ने इसके खिलाफ कभी नहीं कहा। लेकिन जब वही लोग चुनाव हारते हैं, तो वे ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं। यह देश और जनता की समझ के विपरीत है, क्योंकि कानून और मशीनें उसी समय लाई गई थीं जब विपक्ष सत्ता में था।

पांच साल की रिसर्च के बाद वीवीपीएटी को लागू किया गया। जब कोई मतदाता ईवीएम में कमल के निशान पर वोट डालता है, तो पास में एक प्रति निकलती है, जिसमें दिखाया जाता है कि आपका वोट किस उम्मीदवार को गया। इसके बावजूद विपक्ष ने आरोप लगाना जारी रखा। 2017 में चुनाव आयोग ने तीन दिन तक अपना ऑफिस खोलकर सभी पार्टियों, टेक्नोक्रेट्स और वैज्ञानिकों को मौका दिया कि वे ईवीएम हैक करके दिखाएं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका। इसके बावजूद विपक्ष केवल प्रेस में आरोप लगाता रहा, न कि अदालत में या चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव जीतने का तरीका केवल जनादेश के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी अन्य प्रक्रिया या आरोप

पर आधारित।

विपक्ष यह दावा करता है कि प्रधानमंत्री के शेड्यूल के आधार पर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। सभी सांसदों से अनुरोध है कि चुनाव से एक महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का शेड्यूल देखें। लेकिन यह चुनाव निर्धारित करने का आधार नहीं बनता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आजादी के बाद से सबसे अधिक जनसंपर्क और प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी या वेकेशन नहीं ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के बाहर खुद जांच करवाई। मई 2014 के बाद चुनाव सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितने सुझाव या आवेदन दिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, चुनाव सुधार पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होती है, चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को सुझाव भेजता है और फिर विधि मंत्रालय संसद के समक्ष कानून का प्रस्ताव रखता है। मई 2014 से आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रस्ताव नहीं दिया। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में नियम तय होते हैं और सभी दलों को बकायदा पत्र भेजकर समय दिया जाता है। यह एक औपचारिक और पारदर्शी प्रक्रिया है और इसे विपक्ष समझने से इनकार करता है।

73 वर्षों तक देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। पहले नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री के माध्यम से होती थी और राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। विपक्ष के नेता को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल करने का काम मोदी सरकार ने किया है, कांग्रेस के दौर में अकेले प्रधानमंत्री ही यह फैसला करते थे।

1950 से 2023 तक कोई विशेष कानून नहीं बना था। 2023 में कानून बन गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, एक मंत्री और तीन अन्य लोग मिलकर चर्चा कर मेरिट के आधार पर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। चुनाव आयोग ने 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का निर्णय लिया, जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर ही चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। 1991 में बने इस नियम के अनुसार, चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज को सर्कुलर के माध्यम से इस धारा के साथ संरेखित कर दिया, यानी 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं उठाया जा सकता।

जब सीसीटीवी फुटेज प्रक्रिया में शामिल किया गया, तब स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग ने कहा था कि यह संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा है। आंतरिक प्रबंधन के दस्तावेज पर कोई पुनर्मतदान की अर्जी क्यों दी जाएगी। मतदाता मतदान में यदि चुनाव सही नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग का निर्णय सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही होता है। पहले यह मुख्य तकनीकी सुधारों के तहत किया जाता था, लेकिन अब यह केवल आंतरिक प्रबंधन के लिए मान्य है।

विपक्ष चाहे 200 बार भी बहिष्कार कर ले, लेकिन अवैध घुसपैठिए को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। यह एनडीए की स्पष्ट नीति है, डिटेक्ट यानी ढूंढ़ना, डिलीट यानी मतदाता सूची से नाम हटाना और डिपोर्ट यानी उन्हें वापस भेजना। यह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी की जाएगी। पहले उन्हें सामान्य नागरिक जैसा दर्जा देना, फिर मान्यता प्रदान करना और अंत में उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर चुनावी लाभ प्राप्त करना। यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता और उनके पार्टी के सिद्धांतों के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत मान्यता भी है कि जनसांख्यिकी में बड़ा परिवर्तन देश के लिए गंभीर खतरा है। देश पहले ही जनसंख्या के आधार पर विभाजन देख चुका है और आने वाली पीढ़ियों को इसका पुनरावृत्ति नहीं दिखना चाहिए। इसलिए घुसपैठ को रोकना अत्यंत आवश्यक है। घुसपैठ बांग्लादेश की सीमा से हो रही है, जो कुल 2216 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 1653 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है और 563 किलोमीटर शेष है, वह भी केवल एक राज्य बंगाल में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सीमा पूरी तरह सुरक्षित है, केवल बंगाल में काम रोककर रखा गया है। टीएमसी राहुल गांधी के साथ घुसपैठियों को बचाने की यात्रा में शामिल होकर खुलकर सामने आ चुकी है। यदि वे भी अवैध घुसपैठियों को बचाएंगे तो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी होगी।

देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों पर निर्भर होकर किया जाता है, लेकिन यह तरीका देश के हितों को गहरे नुकसान पहुँचाता है। बिहार की जनता ने घुसपैठियों को बचाने वाली राजनीति के खिलाफ बड़ा जनादेश दिया है और बंगाल भी आने वाले दिनों में यही करने जा रहा है।

क्या इस देश में कोई कानून बनाया गया है कि आरएसएस विचारधारा रखने वाला व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रह सकता? इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस विचारधारा वाला है, देश का गृहमंत्री भी आरएसएस विचारधारा वाला है और दोनों जनता के जनादेश से बने हैं, राहुल गांधी और विपक्ष की कृपा से नहीं।

1969 में देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उस समय इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के भीतर संघर्ष कर रही थीं। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार श्री संजीव रेड्डी को बनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी ही पार्टी के मैनडेट को नकार दिया और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग अंतरात्मा की आवाज से करनी चाहिए और उन्होंने वही किया। इसके बाद स्थिति यह बनी कि संजीव रेड्डी अल्पमत में आ गए जबकि उनका बहुमत बहुत अधिक था। जीत सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों से समझौता किया और देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों, शिक्षा संस्थानों और अन्य संस्थाओं पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को बैठाने का कार्य किया। वहीं से देश के विमर्श को बदलने का काम किया गया और वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, जो इस देश की प्रकृति, स्वभाव और जनता के अनुकूल कभी नहीं रही। यही कारण है कि वामपंथ लगभग लुप्त हो गया। इंदिरा गांधी ने देश के युवाओं को वामपंथी विचारधारा की ओर मोड़ने का काम किया, जिसे 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतांत्रिक तरीके से फिर से परिष्कृत और सुधारने का कार्य किया है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि आरएसएस विचारधारा वाले लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा रहा है। इसमें आपत्ति की क्या बात है? कोई कानून नहीं है जो आरएसएस विचारधारा वाले व्यक्ति को पद पर बैठने से रोकता हो। आरएसएस की विचारधारा है देश के लिए जीना-मरना, देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाना और संस्कृति का झंडा बुलंद करना। यदि यह विचारधारा है, तो इसमें गलत क्या है। वे डरने वालों में से नहीं हैं।

विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश, सीएए और ट्रिपल तलाक का विरोध किया, इसी वजह से विपक्ष की हार हुई। अब विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 60 करोड़ गरीबों के घरों तक योजनाएँ पहुँचाईं, गैस, पानी, शौचालय, पांच किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की दवाइयाँ पहुंचाई। देश का 40 साल में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसे 11 वर्षों में तीन गुना बढ़ाया गया। यही कारण है कि जनता ने भाजपा सरकार को पुनः समर्थन दिया। 140 करोड़ लोगों का जनादेश ईश्वर का आदेश है और जनता का निर्णय सर्वोच्च होता है। विपक्ष ''चोरी और लूट'' जैसी भाषा का प्रयोग करता है, जबकि जनता सब देख रही है। ▪

शहादत संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक - डॉ. मोहन यादव

- **जन-जन तक पहुंचाएं साहिबजादों के संघर्ष और बलिदान की गाथा**
- **युवाओं को प्रेरित करती रहेगी साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेहसिंह की शहादत**

मुगल शासकों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु श्री गोविन्द सिंह जी महाराज के परिवार एवं दोनों साहिबजादों ने जो सर्वोच्च शहादत दी, उसे दुनिया सदैव स्मरण करती रहेगी। दोनों साहिबजादों के साथ मुगलों द्वारा की गई अमानवीय क्रूरता को स्मरण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविन्द सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान का मार्ग दिखाया। धन्य है वह भारत माता, जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविन्द सिंह जी एवं उनके पश्चात् गुरुओं तक संघर्ष और बलिदान की यह परंपरा निरंतर चलती रही। चाहे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, आजाद हिंद फौज का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हो अथवा 1942 का आंदोलन, प्रत्येक चरण में सिख बंधुओं के त्याग और संघर्ष ने राष्ट्र को प्रेरणा दी है। किंतु साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी की शहादत वास्तव में अद्भुत, अनुपम और प्रेरणास्पद है। दोनों साहिबजादों ने त्याग, समर्पण और बलिदान की जो अद्वितीय मिसाल स्थापित की है, वह हमारी युवा पीढ़ी को वीरता, ईमानदारी, आत्मसम्मान और दृढ़ता के साथ मूल्य-आधारित जीवन जीने की सतत् प्रेरणा देती रहेगी।

26 दिसंबर, साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस घोषित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा कौन-सा बाल दिवस होना चाहिए, जिस पर देश को गौरव की अनुभूति हो और आने वाली पीढ़ियां जिनसे प्रेरणा लें। केवल प्रतीकात्मक आयोजनों से कोई दिन बाल दिवस नहीं बन जाता। 26 दिसंबर वह दिन है, जब मात्र 6 और 9 वर्ष की आयु में दो नन्हे साहिबजादों ने विधर्मियों के सामने झुकने से इनकार करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। त्याग, संघर्ष और बलिदान की इस गौरवशाली पृष्ठभूमि वाला 26 दिसंबर ही वीर साहिबजादों की स्मृति में मनाया जाने वाला वास्तविक बाल दिवस है, जिसे देश वीर बाल दिवस के रूप में मना रहा है। ▪

साहिबजादों की शहादत अविस्मरिणीय - हेमंत खण्डेलवाल

- **वीर बाल दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान और धर्मनिष्ठता का संदेश देता है।**
- **साहिबजादों की शहादत से देशभक्ति और संस्कारों की सीख मिलती है।**

26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी की अमर शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। मात्र 6 और 9 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने मुगल शासकों के अत्याचारों के सामने डटकर खड़े होकर अपने धर्म की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु गोबिन्द सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जिसने राष्ट्र और धर्म के लिए सर्वोच्च त्याग का अर्थ सिखाया। साहिबजादों का साहस, शौर्य और आत्म बलिदान आज की पीढ़ी के लिए राष्ट्र भक्ति, आत्म सम्मान और धर्म निष्ठा की अमिट प्रेरणा है। यह दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि संकल्प का दिवस है, जो हमें राष्ट्र प्रेम, धर्म रक्षा और आत्म सम्मान के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के उन सभी वीर शहीदों को सम्मान मिल रहा है, जिनके बलिदान को वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। वीर बाल दिवस का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को यह बताना है कि बलिदान, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी यह संदेश देते हैं कि वीर बाल दिवस ऐसा अवसर बने, जिससे भावी पीढ़ी को देश और समाज के लिए जीने की प्रेरणा मिले। वीर बाल दिवस हम सभी को संकल्प दिलाता है कि हमारी नई पीढ़ी भी साहिबजादों के बताए मार्ग पर चले। साहिबजादों की शहादत को यह देश कभी नहीं भूलेगा। हम सबका दायित्व है कि हम अपने बच्चों को उनकी शहादत से प्रेरणा लेने और राष्ट्र व समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करने की सीख दें। ▪

अदम्य साहस और अटूट आस्था की मिसाल हैं वीर साहिबजादे- हितानंद

- **वीर साहिबजादों की गाथा युगों तक मार्गदर्शक बनी रहेगी।**

जिन वीर साहिबजादों ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए बाल अवस्था में ही बलिदान की पराकाष्ठा को छू लिया, उनका साहस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मात्र 6 और 9 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने ऐसा अद्वितीय साहस प्रदर्शित किया, जो हिमालय से भी ऊँचा था। धर्म, कर्तव्य और देशभक्ति के मार्ग पर अडिग रहकर उन्होंने अत्याचार के सामने कभी शीश नहीं झुकाया। बाल अवस्था में भी जिस दृढ़ आस्था, अपूर्व आत्मबल और अद्वितीय वीरता के साथ साहिबजादों ने क्रूर अत्याचारों का सामना किया, वह मानव इतिहास में अद्वितीय और प्रेरणास्पद है। उनकी अमर गाथा आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम, त्याग और आत्म सम्मान की चेतना जागृत करती है तथा युगों-युगों तक राष्ट्र भक्ति, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।

वीर बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को यह संदेश देना है कि आयु भले ही छोटी हो, किंतु विचार, साहस और संकल्प महान हो सकते हैं। यह दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी में नैतिक मूल्यों, वीरता और देशभक्ति की भावना जगाने का सशक्त माध्यम है। पूर्व में बाल दिवस को एक व्यक्तित्व विशेष के जन्मदिन तक सीमित रखा गया था, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविन्द सिंह जी के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को राष्ट्र के सामने जीवंत रखने के लिए वीर बाल दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। साहिबजादों ने विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी शीश नहीं झुकाया और भारत की एकता, अखंडता तथा सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ▪

प्राकृतिक खेती से किसानों की समृद्धि - अमित शाह

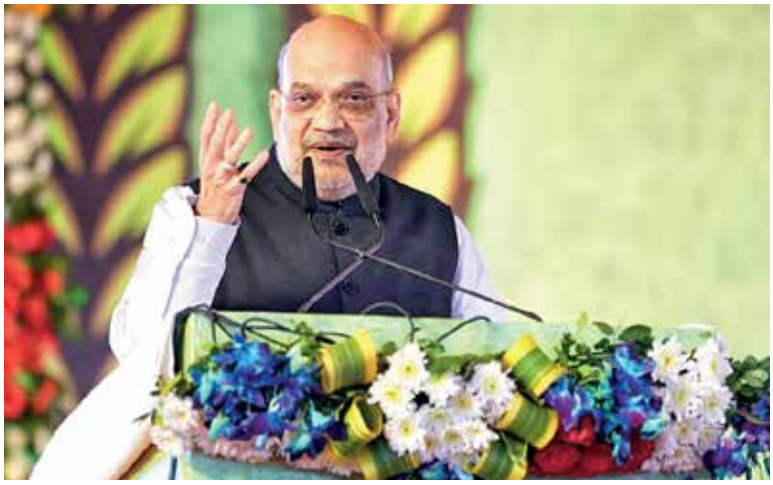

प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ेगी, पानी बचेगा और अनाज खाने वाले लोगों को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और इससे उनका उत्पादन बढ़ रहा है।

प्राकृतिक खेती एक ऐसा परंपरागत प्रयोग है जिसे हम भूल चुके हैं। प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जिसमें गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं होने देती और उपज भी शुद्ध होती है। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद और पेस्टिसाइड्स के बिना प्राकृतिक खेती होती है।

प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ेगी, पानी बचेगा और अनाज खाने वाले लोगों को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और इससे उनका उत्पादन बढ़ रहा है।

प्राकृतिक खेती के उत्पादों के सर्टिफिकेशन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गठित सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से दो बड़ी कोऑपरेटिव्स ने प्राकृतिक खेती की उपज का सर्टिफिकेशन, विश्व की सबसे आधुनिक लैब में इसका परीक्षण, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात की व्यवस्था की है। आने वाले दिनों में देशभर में 400 से अधिक प्रयोगशालाएं किसानों को सर्टिफिकेट देंगी कि उनका खेत और उपज दोनों प्राकृतिक हैं जिससे किसानों की आय लगभग डेढ़ गुना बढ़ेगी। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का दुनियाभर में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूरी दुनिया के बाजार में हमारे किसानों का ऑर्गेनिक उत्पाद अच्छे से पहुंचे इसके लिए सर्टिफिकेशन, साइंटिफिक टेस्टिंग, आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए और इन सभी के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र धीरे धीरे एक विकसित क्षेत्र बनता जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट रीवा में है, रीवा से प्रयागराज या जबलपुर हो, बहुत अच्छी चार लेन की सड़कों का विकास हुआ है। अटल जी ने न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता को बहुत महत्व दिया। अटल जी एक ऐसे नेता की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने जो बोला वह कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका वक्तव्य और जीवन एक समान होते हैं। ▪

राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र -निर्माण के लिए - पीएम मोदी

राष्ट्र प्रेरणा स्थल, उस सोच का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्म सम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची हैं, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद हैं।

25 दिसंबर का दिन, देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की, और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म-जयंती है। महाराजा बिजली पासी ने, वीरता, सुशासन और समावेश की जो विरासत छोड़ी, उसको हमारे पासी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया है। ये भी संयोग ही है कि, अटल जी ने ही वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल, उस सोच का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्म सम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची हैं, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद हैं। अटल जी ने लिखा था,

नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन-मन,
जीवन को शत-शत आहुति में, जलना होगा,
गलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल, हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास, राष्ट्र-निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे, जिन्होंने भारत में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी, जम्मू-कश्मीर में ये व्यवस्था, भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि, हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है।

स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में, डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्म निर्भरता की नींव रखी थी। उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी थी। यानी भारत में औद्योगीकरण की बुनियाद रखी थी। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनियाभर में पहुंच रहा है। छोटे-छोटे उद्योगों, छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, दुनिया भर में डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा।

दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना, अंतिम पंक्ति में खड़े ''अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान'' से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने ''एकात्म मानववाद'' का दर्शन भी दिया, जहाँ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, सबका विकास हो। दीन दयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है, तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को, बिना भेदभाव, पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और

गैस कनेक्शन मिल रहा है, करोड़ों लोगों को पहली बार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज मिल रहा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, तो पंडित दीन दयाल जी के विजन के साथ न्याय हो रहा है।

बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को परास्त किया है, गरीबी को हराया है। ये इसलिए संभव हुआ, क्योंकि भाजपा सरकार ने, जो पीछे छूट गया था, उसे प्राथमिकता दी, जो अंतिम पंक्ति में था, उसे प्राथमिकता दी।

2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी ऐसे थे, जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे। आज करीब 95 करोड़ भारतवासी, इस सुरक्षा कवच के दायरे में हैं। जैसे बैंक खाते सिर्फ कुछ ही लोगों के होते थे, वैसे ही, बीमा भी कुछ ही सम्पन्न लोगों तक सीमित था। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक बीमा सुरक्षा पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई, इससे मामूली प्रीमियम पर दो लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित हुआ। इस योजना से 25 करोड़ से ज्यादा गरीब जुड़े हैं। इसी तरह, दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है। इससे भी करीब 55 करोड़ गरीब जुड़े हैं। ये वो गरीब देशवासी हैं, जो पहले बीमा के बारे में सोच भी नहीं पाते थे।

इन योजनाओं से करीब-करीब 25 हजार करोड़ रुपए का क्लेम, इन छोटे-छोटे परिवार के छोटे-छोटे जिंदगी के गुजारे करने वाले, सामान्य गरीब परिवारों तक 25 हजार करोड़ रूपयों का लाभ पहुंचा है। यानी संकट के समय ये पैसा गरीब परिवारों के काम आया है।

अटल जी की जयंती का दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक, देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था। लेकिन अटल जी ने, सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। उस समय जिस विशेष कार्ड के लिए काम शुरु हुआ था, जो आज आधार के रूप में, विश्व विख्यात हो चुका है। भारत में टेलिकॉम क्रांति को गति देने का श्रेय भी अटल जी को ही जाता है। उनकी सरकार ने जो टेलिकॉम नीति बनाई, उससे घर-घर तक फोन और इंटरनेट पहुंचाना आसान हुआ, और आज भारत, दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल और इंटरनेट यूजर वाले देशों में से एक है।

आज अटल जी जहां होंगे, इस बात से प्रसन्न होंगे कि, बीते 11 वर्षों में भारत, दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। और जिस यूपी से वो सांसद रहे, वो यूपी आज भारत का नंबर वन मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग राज्य है।

कनेक्टिविटी को लेकर अटल जी के विजन ने, 21वीं सदी के भारत को शुरुआती मजबूती दी। अटल जी की सरकार के समय ही, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का अभियान शुरु किया गया था। उसी समय स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी हाईवे के विस्तार पर काम शुरु हुआ था।

साल 2000 के बाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी हैं। और इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 10-11 साल में बनी हैं।

आज हमारे देश में अभूतपूर्व गति से एक्सप्रेस-वे बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है। वो अटल जी ही थे, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क, लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। भाजपा-NDA सरकार ने सुशासन की जो विरासत बनाई है, उसे आज भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें, नए आयाम, नया विस्तार दे रही है।

डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीन दयाल जी, अटल जी, इन तीन महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिमाएं, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं, हमें नई ऊर्जा से भर रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि, आजादी के बाद, भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हों, सरकारी योजनाएं हों, सरकारी संस्थान हों, गली, सड़क, चौराहे हों, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार, मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है।

कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने ये पाप किया, और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया, लेकिन भाजपा ने बाबा साहेब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक, बाबा साहेब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं।

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों में बंटे हमारे देश को एक किया था, लेकिन आजादी के बाद, उनके काम और उनके कद, दोनों को छोटा करने का प्रयास किया गया। ये भाजपा है जिसने सरदार साहेब को वो मान-सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे। भाजपा ने ही सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, एकता नगर के रूप में एक प्रेरणा स्थली का निर्माण किया। अब हर साल वहां 31 अक्टूबर को देश राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य आयोजन करता है।

हमारे यहां दशकों तक आदिवासियों के योगदान को भी उचित स्थान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है।

देशभर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, महाराजा सुहेलदेव का स्मारक, तब बना जब भाजपा सरकार बनी। निषादराज और प्रभु श्रीराम की मिलन स्थली को अब जाकर के मान-सम्मान मिला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर चौरी-चौरा के शहीदों तक, मां भारती के सपूतों के योगदान को भाजपा सरकार ने ही पूरी श्रद्धा और विन्रमता से याद किया है।

परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, ये असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए, परिवारवादियों के लिए, दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरु किया। आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था, उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजर अंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री, चाहे कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है।

कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा। लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान, नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, ये दुनिया में यूपी की नई पहचान के प्रतीक बन रहे हैं। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे आधुनिक निर्माण, उत्तर प्रदेश की नई छवि को और अधिक रोशन बनाते हैं। ▪

विचार अटल थे, संकल्प मोदी जी ने साकार किए

हेमन्त खण्डेलवाल

अटल जी का व्यक्तित्व विचार और संवेदना का दुर्लभ संगम था। वे दृढ़ राष्ट्रवादी थे, किंतु संवाद और सहमति के पक्षधर भी। सत्ता में रहते हुए भी उनकी भाषा में मर्यादा और व्यवहार में विनम्रता रही।

25 दिसंबर केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की वैचारिक यात्रा का स्मरण दिवस है। यह वह दिन है, जब राष्ट्र अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे युगद्रष्टा नेता की जन्म जयंती मनाता है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष हमें उनके विचारों, संकल्पों और सपनों को और गहराई से आत्मसात करने का अवसर देता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति वर्ष के रूप में इस कालखंड को मनाना, अतीत के गौरव को वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य के संकल्प से जोड़ने का सशक्त प्रयास है।

अटल जी का व्यक्तित्व विचार और संवेदना का दुर्लभ संगम था। वे दृढ़ राष्ट्रवादी थे, किंतु संवाद और सहमति के पक्षधर भी। सत्ता में रहते हुए भी उनकी भाषा में मर्यादा और व्यवहार में विनम्रता रही। कविता उनकी आत्मा थी और राष्ट्रसेवा उनका जीवन-संकल्प। यही कारण है कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा के प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने सुशासन को व्यवहार में उतारा। पोखरण परमाणु परीक्षणों से भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता स्थापित हुई, तो कारगिल जैसे कठिन समय में उन्होंने पूरे देश को एकजुट नेतृत्व दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूरसंचार क्षेत्र में किए गए सुधार- ये सभी उस विकसित भारत की आधारशिला बने, जिसकी दूरदृष्टि अटल जी ने वर्षों पहले देख ली थी।

अटल बिहारी वाजपेयी जी का मध्यप्रदेश से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं, ऐतिहासिक और भावनात्मक भी था। ग्वालियर को कर्मभूमि बनाकर उन्होंने इस प्रदेश से आत्मीय संबंध स्थापित किया। ग्वालियर की जनता ने उन्हें लोकसभा में भेजा, तब यह केवल एक चुनावी विजय नहीं थी, बल्कि कठिन समय में दिया गया वह विश्वास था जिसने अटल जी को राष्ट्रीय नेतृत्व की नई ऊर्जा प्रदान की।

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि ग्वालियर को यह भी गौरव प्राप्त है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित ''एकात्म मानवदर्शन'' की वैचारिक धारा को यहीं प्रथम स्वर मिला। अटल जी की विचारशील राजनीति और एकात्म मानवदर्शन की यह संगति ग्वालियर को भारतीय लोकतंत्र की वैचारिक चेतना का विशेष केंद्र बनाती है।

अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर ग्वालियर की धरती का पुनः राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है। 25 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का ग्वालियर आगमन और ''अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट-2025'' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी सहभागिता, अटल जी की विकास-दृष्टि को वर्तमान भारत से जोड़ने वाला सशक्त संदेश है। जिस ग्वालियर ने अटल जी को राष्ट्र नेतृत्व की नई दिशा दी थी, वही ग्वालियर आज उनके विचारों के अनुरूप विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय का साक्षी बन रहा है।

अटल जी का सपना था- एक ऐसा भारत जो मजबूत भी हो और संवेदनशील भी, जो विकास करे, पर मूल्यों से विमुख न हो, जो आत्मनिर्भर बने, पर विश्व के साथ संवाद बनाए रखे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ''विकसित भारत@2047'' की दिशा में आगे बढ़ता राष्ट्र उसी अटल दृष्टि का आधुनिक और सशक्त विस्तार है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत आधारभूत संरचना और वैश्विक मंच पर भारत की निर्णायक भूमिका ये सभी अटल जी के स्वप्न को साकार करते हुए दिखाई देते हैं।

अटल जी के विचारों की दृढ़ता को यदि किसी ने निकट से जिया है, तो वह हमारी पीढ़ी है। मुझे स्मरण है वर्ष 1980 का वह समय, जब मैं मात्र 16 वर्ष का था। उसी वर्ष मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विजय खंडेलवाल जी बैतूल जिले के पहले निर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष बने। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। संख्या बल सीमित था, कार्यकर्ताओं पर दबाव था, सत्ता का आकर्षण त्याग कर हम एक कठिन वैचारिक यात्रा पर निकले थे।

उसी दौर की एक स्मृति आज भी मन में ताजा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे घर आए थे, साधारण माहौल, खाने की मेज पर बातचीत, कभी हल्की मुस्कान, कभी आत्मीय ठहाका। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी बोझिल नहीं दिखते थे। चुनौतियाँ थीं, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा नहीं होती थी। वे बड़े सहज भाव से कहते थे कि आज हम कम जरूर हैं, पर हमारा भरोसा मजबूत है, और यही भरोसा आगे चलकर ताकत बनेगा। उनका विश्वास यही था कि यह रास्ता भले कठिन हो, पर सही है- क्योंकि यह सत्ता का नहीं, राष्ट्रसेवा का मार्ग है।

उनकी वही सहजता, आत्मबल और भविष्य पर अडिग भरोसा हम जैसे युवाओं के लिए उस समय सबसे बड़ा संबल बन गया।

आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो लगता है कि अटल जी की वही अडिग दृष्टि आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह केवल संगठनात्मक विस्तार नहीं, बल्कि विचार की विजय है। भाजपा आज सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि जनकल्याण, लोककल्याण और सेवा- आधारित सुशासन का पर्याय बन चुकी है। अटल जी का वह विश्वास, जो 1980 में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में व्यक्त हुआ था, आज विकसित भारत के संकल्प के रूप में साकार खड़ा है- आत्मविश्वास से भरा, संकल्पबद्ध और राष्ट्रहित को समर्पित।

अटल स्मृति वर्ष हम सभी के लिए अवसर है अपने सार्वजनिक जीवन, सामाजिक आचरण, और राष्ट्रीय कर्तव्यों में उन मूल्यों को अपनाने का, जिनका प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे।

उनके विचारो को स्मरण में नहीं आचरण में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ▪

(लेखक भाजपा मप्र के अध्यक्ष हैं।)

हमारे अटलजी-राष्ट्र सेवा, सुशासन के युगपुरुष

हितानंद शर्मा

भारत ने करवट ले ली है। देश अब अतीत की कमियों को दूर कर स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ 'विकसित भारत' के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को और आगे ले जा रहे हैं। अटलजी के स्वप्नों का लोक-कल्याणकारी, शक्ति संपन्न, अडिग, अजेय, समर्थ और विश्व का मार्गदर्शन करने वाले राष्ट्र का उत्थान होते दुनिया देख रही है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए 25 दिसंबर जननायक की जन्मतिथि मात्र नहीं है। यह उस विचार, संस्कार और राजनीतिक परंपरा का स्मरण दिवस है, जिसने सत्ता को सेवा, राजनीति को मर्यादा और राष्ट्रनीति को नैतिक बल प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर जनसंघ और फिर भाजपा की उनकी राजनैतिक यात्रा सर्वसमावेशी व्यक्तित्व की प्रतीक रही है। यही कारण है कि विश्व ने उन्हें अजात शत्रु के रूप में जाना। अटल जी का जन्म दिवस अटल स्मृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि भारत केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनके विचारों और मूल्यों का भी स्मरण करता है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में थे जिनका व्यक्तित्व सत्ता से बड़ा और समय से आगे दिखाई देता था। वे ऐसे राजनेता थे जो विचार धारा में अडिग रहते हुए भी संवाद में उदार थे। अटल जी के लिए राजनीति लोकतांत्रिक विमर्श की साधना की भांति रही। संसद में भले ही विषय कितना ही संवेदनशील क्यों न हो अटलजी का वक्तव्य कभी कटु नहीं होता था। वे शब्दों से आघात नहीं करते थे, बल्कि तर्क, तथ्य और भाव से अपनी बात रखते थे। संसदीय परंपरा में अटल बिहारी वाजपेयी का आचरण एक आदर्श की तरह दिखाई देता है। उनकी यह विशेषता भारतीय लोकतंत्र को एक नैतिक ऊँचाई प्रदान करती है जिसमें असहमति शालीनता से व्यक्त की जा सकती है और विरोध भी गरिमामय तरीके से किया जा सकता है।

25 दिसम्बर 1924 को ग्वालियर में जन्में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र सेवा करते हुए एक प्रकाशवान नक्षत्र की तरह भारतीय लोकतंत्र में प्रेरणा की तरह स्थापित हो गए। अटल जी को भाजपा का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है। मुंबई अधिवेशन में दिया गया उनका वह भाषण प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए मानों संकल्प और संबल बन गया जिसमें उन्होंने कहा था - अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और उनकी वाणी सत्य हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूर्य अपनी छंटा बिखेर रहा है, कमल खिल रहा है और अंधेरा छंट चुका है।

अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वैचारिक परंपरा से आए थे। उन्होंने राजनीति में रहते हुए विचारधारा को समावेशी राष्ट्रीयता का स्वरूप दिया। वे जानते थे कि राष्ट्रनिर्माण के लिए संवाद, विश्वास और सहभागिता आवश्यक तत्व हैं। उनकी राजनीति में राष्ट्र सर्वोपरि था और राष्ट्र का अर्थ केवल सीमाएँ नहीं बल्कि जनता, संस्कृति और मानवीय संवेदना भी थी। यही कारण है कि वे दृढ़ निर्णय लेने वाले नेता थे और करुणा से भरे कवि भी थे।

प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल आज के भारत के विकास की नींव का कालखंड माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश को भौगोलिक रूप से जोड़ा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा, किसान फसल बीमा योजना ने किसानों को संबल प्रदान किया, दूरसंचार क्रांति ने भारत को डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर किया। अटलजी जब 1996 में देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने तो भारत की जनता ने महसूस किया कि लोकतंत्र की अवधारणा के अनुसार जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार सही अर्थों में क्या होती है। जनता से जाना कि दीनदयाल जी और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की वैचारिक विरासत का सुशासन सही अर्थों में क्या होता है।

अटलजी गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री थे। इससे पूर्व राजनीतिक दलों के गठबंधन इसलिए सफल नहीं हो पाते थे क्योंकि आशंकाएं, अविश्वास, महत्वाकांक्षाएं और संवाद की कमी उन्हें मजबूत नहीं होने देती थी। परिणाम स्वरूप गठबंधन की सरकारें अस्थिर रहती थीं। यह अटलजी की ऐतिहासिक सफलता थी कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति को स्थायित्व दिया और यह भी सिद्ध किया कि सहयोग से चलने वाली सरकारें भी निर्णायक और प्रभावी हो सकती हैं। यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

एक समर्थ, सक्षम और शक्तिशाली भारत उनके स्वप्नों में रहता था। वे जानते थे कि राष्ट्रहित में कठोर निर्णय भी आवश्यक हैं और मानवीय पहल भी जरूरी हैं। राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण-2 का निर्णय लेकर अटलजी ने भारत की सामरिक क्षमता को वैश्विक मंच पर दमदार तरीके से स्थापित किया। यह निर्णय साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। अटलजी ने लाहौर बस यात्रा कर यह संदेश भी दिया कि भारत की नीति में शक्ति का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि शांति है। वहीं करगिल घाटी से दुश्मन की सेनाओं को खदेड़ने की उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए उन्हें युगों-युगों तक याद किया जाएगा।

केवल राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। वे एक संवेदनशील कवि थे, जिनकी कविताओं में राष्ट्र गुनगुनाता था। उनकी रचनाओं में आशा, विश्वास, दृढ़ता के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प भी है। वे शब्दों के माध्यम से समाज का जागरण करते थे तो भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त भी करते थे। आज भी उनकी कविताएँ भारतीय चेतना को जागृत करती हैं और यह याद दिलाती हैं कि राष्ट्र केवल वर्तमान नहीं बल्कि इतिहास की स्मृति और भविष्य के संकल्पों दोनों का सम्मिलित स्वरूप है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस दृढ़ संकल्प के साथ देश को एक सक्षम और निर्णायक नेतृत्व प्रदान करते हुए सच्चे अर्थों में 21 वीं सदी भारत की सदी बनाने के अटल जी के स्वप्न को साकार कर रहे हैं। निर्णायक और पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था और तकनीकि आधारित पारदर्शी लोक कल्याणकारी योजनाएं अटल जी की विरासत को संभालने और उसे आगे ले जाने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आज भारत का जो चित्र सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व पटल पर उभर रहा है। अटल स्मृति वर्ष और 25 दिसंबर हमें यह विचार करने का अवसर देते हैं कि हम अटल जी के बताए मार्ग पर कितनी दृढ़ता से चलते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं, राष्ट्रीयता, व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, सकारात्मकता और धैर्य के साथ राष्ट्र व समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करना है। अटल जी किसी एक दल या कालखंड के नहीं, बल्कि समूचे भारतीय लोकतंत्र की धरोहर हैं। उनका स्मरण केवल अतीत की ओर देखने का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का अवसर है। 25 दिसंबर और अटल स्मृति वर्ष हमें यह संकल्प दिलाते हैं कि राजनीति राष्ट्रसेवा और लोककल्याण का साधन है। ▪

(लेखक भाजपा मप्र के संगठन महामंत्री हैं)

'विकसित भारत' का संकल्प पूरा होगा

- राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, साइंस लैब्स से लेकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है।
- 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान, देश के हर कोने से माँ भारती के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आईं।
- वर्ल्ड चैंपियन शिप में पैरा-एथलीटों ने कई मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि जोश और पक्के इरादे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती।
- विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों, नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विस्तार ने दुनिया भर के देशों को बहुत प्रभावित किया है।
- अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ''राष्ट्रीय युवा दिवस'' मनाया जाएगा।
- ''स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025'' के दौरान, छात्रों ने 80 से ज्यादा सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर काम किया।
- मणिपुर के मोइरांगथेम ने सोलर पैनल लगाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया और इस कैंपेन की वजह से आज उनके इलाके में सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है।
- 'तमिल सीखें - तमिल कराकलम थीम' के तहत, वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में खास कैंपेन चलाए गए।

साल 2026 दस्तक देने वाला है, और मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं - कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां, जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक। भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल 'ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान देश के कोने-कोने से माँ भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किये।

2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक। भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी।

यही जज्बा तब भी देखने को मिला, जब 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि '#VandeMataram150' के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष Cricket team ने ICC Champions Trophy जीती। महिला Cricket team ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने Women's Blind T20 World Cup जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व Championship में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौंसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने, जो International Space Station तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य-जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं, जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।

आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी

वजह है, हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए-नए innovation, technology का विस्तार इनसे दुनियाभर के देश बहुत प्रभावित हैं।

भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे यह पूछते हैं कि nation building में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं? वो कैसे अपने ideas share कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने ideas का presentation कैसे दे सकते हैं? हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है 'Viksit Bharat Young Leaders Dialogue'। पिछले साल इसका पहला edition हुआ था, अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा edition होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय युवा दिवस' मनाया जाएगा। इसी दिन 'Young Leaders Dialogue' का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा Innovation, Fitness, Startup और Agriculture जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने ideas share करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूँ।

मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक quiz competition हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें students ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा।

आज देश के भीतर युवाओं को प्रतिभा दिखाने के नए- नए अवसर मिल रहे हैं। ऐसे बहुत से platforms विकसित हो रहे हैं, जहां युवा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार talent दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक platform है- 'Smart India Hackathon' एक और ऐसा माध्यम जहां ideas, action में बदलते हैं।

'Smart India Hackathon 2025' का समापन इसी महीने हुआ है। इस Hackathon के दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर students ने काम किया। Students ने ऐसे solution दिए, जो real life challenges से जुड़े थे। जैसे traffic की समस्या है। इसे लेकर युवाओं ने Smart Traffic Management' से जुड़े बहुत ही interesting perspective share किए। Financial Frauds और Digital Arrests जैसी चुनौतियों के समाधान पर भी युवाओं ने अपने ideas सामने रखे। गाँवों में digital banking के लिए Cyber Security Framework पर सुझाव दिया। कई युवा agriculture sector की चुनौतियों के समाधान में जुटे रहे। पिछले 7-8 साल में 'Smart India Hackathon' में, 13 लाख से ज्यादा students और 6 हजार से ज्यादा Institutes हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैंकड़ों problems के सटीक solutions भी दिए हैं। इस तरह के Hackathons का आयोजन समय-समय पर होता रहता है। युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन Hackathons का हिस्सा जरूर बनें।

आज का जीवन Tech-Driven होता जा रहा है और जो परिवर्तन सदियों में आते थे वो बदलाव हम कुछ बरसों में होते देख रहे हैं। कई बार तो कुछ लोग चिंता जताते हैं कि Robots कहीं मनुष्यों को ही न Replace कर दें। ऐसे बदलते समय में Human Development के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है-नई सोच के साथ नए तरीकों के साथ।

आपने Indian Institute of Science उसका नाम तो जरूर सुना होगा। Research और Innovation इस संस्थान की पहचान है। कुछ साल पहले वहाँ के कुछ छात्रों ने महसूस किया कि पढ़ाई और Research के बीच संगीत के लिए भी जगह होनी चाहिए। बस यहीं से एक छोटी-सी Music Class शुरू हुई। ना बड़ा मंच, ना कोई बड़ा बजट। धीरे-धीरे ये पहल बढ़ती गई और आज इसे हम 'Geetanjali IISc' के नाम से जानते है। यह अब सिर्फ एक Class नहीं, Campus का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, लोक परंपराएँ हैं, शास्त्रीय विधाएं हैं, छात्र यहाँ साथ बैठकर रियाज़ करते हैं। Professor साथ बैठते हैं, उनके परिवार भी जुड़ते हैं। आज दो-सौ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। और खास बात ये कि जो विदेश चले गए, वो भी Online जुड़कर इस Group की डोर थामे हुए हैं।

अपनी जड़ों से जुड़े रहने के ये प्रयास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग-अलग कोनों और वहाँ बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक और उदाहरण जो हमें देश से बाहर ले जाता है - ये जगह है 'दुबई'। वहाँ रहने वाले कन्नड़ा परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा- हमारे बच्चे Tech-World में आगे तो बढ़ रहें हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं? यहीं से जन्म हुआ 'कन्नड़ा पाठशाले' का। एक ऐसा प्रयास, जहां बच्चों को 'कन्नड़ा' पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आज इससे एक हजार से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। वाकई, कन्नड़ा नाडु, नुडी नम्मा हेम्मे। कन्नड़ा की भूमि और भाषा, हमारा गर्व है ।

'जहां चाह, वहाँ राह'। इस कहावत को फिर से सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांगथेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान् मोइरांगथेम जी मणिपुर के जिस दूर-सुदूर क्षेत्र में रहते थे वहाँ बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने Local Solution पर जोर दिया और उन्हें ये Solution मिला Solar Power में। हमारे मणिपुर में वैसे भी Solar Energy पैदा करना आसान है। तो मोइरांगथेम जी ने Solar Panel लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में Solar Power पहुंच गई है। खास बात ये है कि उन्होंने Solar Power का उपयोग Health-Care और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई Health Centers को भी Solar Power मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी-शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है।

आज सरकार 'PM सूर्य घर' मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को Solar Panel लगाने के लिए करीब-करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। मोइरांगथेम जी के ये प्रयास यूं तो व्यक्तिगत प्रयास हैं, लेकिन Solar Power से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं।

आइए अब जरा हम जम्मू-कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, उसकी एक ऐसी गाथा साझा करना चाहता हूँ, जो आपको गर्व से भर देगी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में, जेहनपोरा नाम की एक जगह है। वहां लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। साधारण से टीले किसी को नहीं पता था कि ये क्या है? फिर एक दिन Archaeologist की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया, तो ये टीले कुछ अलग लगे। इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गईं, जमीन की Mapping की गई। और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं। ये इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष हैं। इसी दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर, फ्रांस के एक Museum के Archives में एक पुराना, धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में तीन बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया। ये करीब दो हजार साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जेहनपोरा

का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है, कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी।

अब मैं आपसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर, एक ऐसे प्रयास की बात करना चाहता हूँ, जो दिल को छू लेने वाला है। Fiji में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहाँ की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने Fiji के राकी-राकी इलाके में वहाँ के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला, जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएँ सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा।

देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा 'काशी तमिल संगमम' हुआ।

अगले महीने हम देश का 77वाँ गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं, तो हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन, दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक-नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला, जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी हैं - ओडिशा की पार्वती गिरि जी, 7 जनवरी 2026 में उनकी जन्म-शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में हिस्सा लिया था।

आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की। उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा।

''मूँ पार्वती गिरि जिंकु श्रद्धांजलि अर्पण करुछी''।

(मैं पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ)

ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को ना भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक-नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। आपको याद होगा जब हमारी आजादी के 75 वर्ष हुए थे, तब सरकार ने एक विशेष website तैयार की थी। इसमें एक विभाग 'Unsung Heroes' को समर्पित किया गया था। आज भी आप इस website पर visit करके उन महान विभूतियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी

भूमिका रही है।

'मन की बात' के जरिए हमें समाज की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ICMR यानि Indian Council of Medical Research ने हाल ही में एक report जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ antibiotic दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। report के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे-समझे antibiotic दवाओं का सेवन है। antibiotic ऐसी दवाएं नहीं हैं, जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल Doctor की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियाँ और संक्रमण इन antibiotic दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। Antibiotic दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा - Medicines के लिए Guidance और Antibiotics के लिए Doctors की जरूरत है। यह आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है।

हमारी पारंपरिक कलाएं समाज को सशक्त करने के साथ ही लोगों की आर्थिक प्रगति का भी बड़ा माध्यम बन रही हैं। आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की Lace Craft (लेस क्राफ्ट) की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ रही है। ये Lace Craft (लेस क्राफ्ट) कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी-शक्ति ने इसका संरक्षण किया है। आज इस परंपरा को एक नए रंग रूप के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और NABARD मिलकर कारीगरों को नए design सिखा रहे हैं, बेहतर skill training दे रहे हैं और नए बाजार से जोड़ रहे हैं। नारसापुरम Lace को GI Tag भी मिला है। आज इससे 500 से ज्यादा products बन रहे हैं और ढाई-सौ से ज्यादा गांवों में करीब-करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिल रहा है।

'मन की बात' ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से ना सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में Margaret Ramtharsiem जी उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहाँ के handicraft को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को, एक बड़े vision के साथ देखा और इसी vision के कारण, वो एक handicraft artist से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गईं। आज Margaret जी की unit उसमें 50 से ज्यादा artist काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में, अपने products का एक market भी develop किया है।

मणिपुर से ही एक और उदाहरण सेनापति जिले की रहने वाली चोखोने क्रिचेना जी का है। उनका पूरा परिवार परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है। क्रिचेना ने इस पारंपरिक अनुभव को एक और विस्तार दिया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना passion बनाया। आज वो इस काम से अलग-अलग markets को जोड़ रहीं हैं और अपने इलाके की local communities को भी Empower कर रही हैं।

ये उदाहरण इस बात का पर्याय है कि अगर पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक vision के साथ आगे बढ़ाएं तो ये आर्थिक प्रगति का बड़ा माध्यम बन

जाता है। आपके आसपास भी ऐसी success stories हों, तो मुझे जरूर share करिए।

हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात ये है कि सालभर हर समय देश के किसी-ना-किसी हिस्से में उत्सव का माहौल रहता है। अलग-अलग पर्व-त्योहार तो हैं ही, साथ ही विभिन्न राज्यों के स्थानीय उत्सव भी आयोजित होते रहते हैं। यानि, अगर आप घूमने का मन बनाएं, तो हर समय, देश का कोई-ना-कोई कोना अपने unique उत्सव के साथ तैयार मिलेगा। ऐसा ही एक उत्सव इन दिनों कच्छ के रण में चल रहा है। इस साल कच्छ रणोत्सव का ये आयोजन 23 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। यहाँ कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता दिखाई देती है। कच्छ के सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। रात के समय जब सफेद रण के ऊपर चाँदनी फैलती है, वहाँ का दृश्य अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। रण उत्सव का Tent City बहुत लोकप्रिय है। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले एक महीने में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग रणोत्सव का हिस्सा बन चुके हैं और देश के कोने-कोने से आए हैं, विदेश से भी लोग आए है। आपको जब भी अवसर मिले, तो ऐसे उत्सवों में जरूर शामिल हों और भारत की विविधता का आनद उठाएं।

2025 में 'मन की बात' का ये आखिरी episode है, अब हम साल 2026 में ऐसे ही उमंग और उत्साह के साथ, अपनेपन के साथ अपने 'मन की बातों' को करने के लिए 'मन की बात' के कार्यक्रम में जरूर जुड़ेंगे। नई ऊर्जा, नए विषय और प्रेरणा से भर देने वाली देशवासियों की अनगिनित गाथाओं 'मन की बात' में हम सबको जोड़ती है। हर महीने मुझे ऐसे अनेक संदेश मिलते हैं, जिसमें 'विकसित भारत' को लेकर लोग अपना vision साझा करते हैं। लोगों से मिलने वाले सुझाव और इस दिशा में उनके प्रयासों को देखकर ये विश्वास और मजबूत होता है और जब ये सब बातें मेरे तक पहुँचती हैं, तो 'विकसित भारत' का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। ये विश्वास दिनों दिन मजबूत होता जाता है। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो, आपका और आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो, इसी कामना के साथ इस episode में विदाई लेने से पहले मैं जरूर कहूँगा, 'Fit India Movement' आप को भी fit रहना है। ठंडी का ये मौसम व्यायाम के लिए बहुत उपयुक्त होता है, व्यायाम जरूर करें। आप सभी को 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ▪

अटल जी का योगदान अद्वितीय -मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनकी कर्मभूमि लखनऊ में उन्हें स्मरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ग्वालियर में आयोजित एमपी ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमिपूजन व लोकार्पण हुआ।

श्रद्धेय अटलजी ऐसे व्यक्तित्व थे कि हर राजनीतिक दल का व्यक्ति उनका सम्मान करता था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति में रहते हुए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और एक महान विचारक के रूप में अतुलनीय योगदान दिया। राष्ट्र धर्म के वैचारिक अनुष्ठान के लिए पूर्णकालिक बनकर भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी जब संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे तो हिंदी में अपनी बात रखकर वैश्विक स्तर पर हिंदी व भारत का मान बढ़ाने का कार्य किया। हमारी सरकार द्वारा श्रद्धेय अटल जी के सर्वहारा वर्ग के कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सभी समाज वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनकी जन्मशताब्दी पर उद्योग-रोजगार वर्ष का आयोजन किया गया। हमारी सरकार गौशालाओं के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रीवा के बसामन मामा गौशाला भी गए थे, जहां प्राकृतिक खेती की जाती है। प्राकृतिक खेती से हम जियो और जीने दो के सिद्धांत को भी प्रतिपादित कर रहे हैं। देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने, कारगिल में विजय दिलाने के साथ कई साहसिक निर्णयों के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। अटल जी ने अपने दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप ही पोखरण परमाणु विस्फोट कर सारी दुनिया को अचंभित कर भारत का मान बढ़ाया था।

ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती पर 20 वीं शताब्दी में अटल जी के रूप में जन्मे विराट व्यक्तित्व ने लोक कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। साथ ही लोकतंत्र को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँव-गाँव में विकास का कारवां पहुँच रहा है।

भारत रत्न अटलजी राजनीति के अजातशत्रु थे। उनमें विचारों की दृढ़ता भी अद्वितीय थी। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को सही मायने में अपनाया था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। प्रदेश सरकार ने अटल जी के आदरांजलि स्वरूप उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ गाँवों के समग्र विकास का बीड़ा उठाया है।

अटल जी की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। वर्तमान में 54 लाख हैक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है, जिसे बढ़ाकर 100 लाख हैक्टेयर तक ले जायेंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ''हर हाथ को काम व हर हाथ को पानी मिले''। ▪

सूर्य नारायण का पर्व है मकर संक्रान्ति

मकर संक्रान्ति का हमारे देश में बहुत ज्यादा सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक महत्व है। इसी कारण रामचरित मानस में उल्लेखित है-

माघ मकरगत रबि जब होई।
तीरथपतिहिं आव सब कोई।।
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं।
सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी।।
पूजही माधव पद जल जाता।
परसि अख्रय बटु हरषहिं गाता।।

ऐसा माना जाता है, कि प्रयाग में संगम पर मकर संक्रान्ति के दिन सारे देव-देवियाँ स्नान करने आते है, इसीलिये प्रयाग में इस दिन स्नान करना अत्याधिक पुण्यकारक माना गया है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति होती है, क्योंकि आज ही के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होकर धनु से मकर राशि में प्रविष्ट होते है, जो सूर्य के पुत्र शनि की राशि है। मकर संक्रान्ति का बहुत बड़ा मेला गंगासागर में लगता है, इसके पीछे की एक कथा है, कि मकर संक्रान्ति को ही गंगाजी स्वर्ग से उतर कर भागीरथ जी के पीछे-पीछे चलकर कपिल मुनी के आश्रम में जाकर सागर से मिल गई थी। गंगा जी के इसी पावन जल से राजा सगर के साठ हजार पुत्रों का जो शाप से पीड़ित थे उनका उद्धार हुआ, इसी घटना की याद में ये तीर्थ गंगासागर के नाम से विख्यात हुआ और इसीलिये यहाँ पर विशाल मेले का मकर संक्रान्ति के दिन आयोजन होता है।

प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, जहाँ भक्तगण कल्पवास करते है, यहाँ हर बारह वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जबकि छः वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ लगता है। ऐसा माना जाता है, कि मकर संक्रान्ति से सूर्य की गति तिल-तिल करके बढ़ती है, इसीलिये इस दिन तिल और गुड़ के दान का महत्व है। इस दिन को पंजाब व जम्मू-कश्मीर में 'लोहड़ी' के रूप में मनाते है, इसके पीछे एक लोक कथा है, कि मकर संक्रान्ति के ही दिन कंस ने भगवान श्रीकृष्ण को मारने के लिये लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्रीकृष्ण ने खेल-खेल में ही मार डाला था, इसी घटना की याद में इसे लोहिड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिन्धी समाज भी मकर-संक्रान्ति के एक दिन पूर्व इसे 'लाह-लोही' के रूप में

प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, जहाँ भक्तगण कल्पवास करते है, यहाँ हर बारह वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जबकि छः वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ लगता है।

मनाते है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रान्ति को 'पोंगल' के रूप में मनाते है, जिसमें तिल, चावल व दाल की खिचड़ी बनाते है, क्योंकि वे नई फसल का चावल, दाल, तिल से पूजा करके कृषि देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है, इसी दिन से तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल शुरु होता है। माघ मास के स्नान का प्रारम्भ पौष की पूर्णिमा से प्रारम्भ हो जाता है। भारतीय संवत्सर का ग्यारहवाँ चान्द्रमास और दसवाँ सौर मास 'माघ' कहलाता है। क्योंकि इस माह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसीलिये इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से माघ माह का बहुत महत्व है। इस माह में जल के भीतर डुबकी लगाने से प्राणी पापमुक्त हो जाता है। इस माह की ऐसी विशेषता है, कि इसमें जहाँ कही भी जल हो, वह गंगाजल के समान होता है। इसी प्रसंग में पद्मपुराण में एक कथा का वर्णन है कि प्राचीन काल में नर्मदा जी के तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे उन्हें वेद, पुराणों, ज्योतिष, तर्क, मंत्र, सांख्य, योग व चौसठ कलाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। वे अनेक देशों की भाषा व लिपियाँ भी जानते थे। इतने ज्ञानी होने के बाद भी वे अपने ज्ञान का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिये न करते हुए धन कमाने के लिये करते थे, जिससे उन्होंने कई स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धन कमाते-कमाते वे बूढ़े हो गये और बीमारी ने आ घेरा। तब उनके मन में विवेक का उदय हुआ कि मैंने अपना सारा जीवन धनार्जन में लगा दिया, परलोक की तो सोची ही नहीं, मेरा उद्धार कैसे हो? वे इसी सोच में थे कि इसी दौरान उनका संग्रहित धन भी चोरी हो गया, जिससे उन्हें धन की वास्तविक नश्वरता का बोध भी हुआ। अब उन्हें चिन्ता थी, तो सिर्फ परलोक की। व्याकुलता में उन्हें ये श्लोक याद आया-

माघे निमग्नाः सलिले सुशीते
विमुक्तपापास्त्रिदिवं प्रयान्ति।।

सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया, उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा जी में लगातार नौ दिन तक स्नान किया। दसवे दिन स्नान के बाद उनके प्राणांत हो गये। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, धनार्जन ही किया था, परन्तु माघ मास में स्नान के कारण निर्मल मन से पश्चाताप करते हुए उन्हें देवलोक की प्राप्ति हुई।

भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अन्धकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। सूर्योपासना का पर्व मकर संक्रान्ति हिन्दुओं द्वारा अंग्रेजी कलैन्डर के अनुसार मनाया जाने वाला एकमात्र पर्व है, जो प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है, कि कुल 12 राशियों में से प्रत्येक राशि में सूर्य का भ्रमण काल एक माह तक होता है, इसीलिये प्रत्येक वर्ष सूर्य 14 जनवरी के आस-पास मकर राशि में प्रवेश करता है। यह स्थिति वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित मकर रेखा के उत्तर की ओर सूर्य के प्रवेश की होती है, इसीलिये इसे सूर्य का उत्तरायण में आना भी कहा जाता है, जो धार्मिक आधार पर शुभता का प्रतीक है। ▪

पं. सलिल मालवीय

संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है

पं. दीनदयाल उपाध्याय

भारत के विचारकों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गाना, नाचना, नाटक खेलना मात्र ही संस्कृति है।

यदि यही संस्कृति की परिभाषा है तो इसका प्रचार हमारे पूर्वज ऋषियों, विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों द्वारा न होकर फिल्म अभिनेता तथा अभिनेत्रियों द्वारा ही होगा।

आम लोगों ने यहां संघ कार्य के अनेक रूपों का विचार किया होगा। एक प्रश्न हमारे सामने यह भी आता है कि समय-समय पर हम कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक अधिष्ठान पर खड़ा है। इस दृष्टि से यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि वह संस्कृति क्या है? संघ की प्रतिज्ञा में भी हम ऐसा कहते हैं, 'हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा कर हिंदू समाज की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हम संघ के घटक बने हैं।' बिना संस्कृति संरक्षण के राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती, यह भी हम स्वीकारते हैं।

आखिर संस्कृति है क्या? हम यह भी देखते हैं कि संस्कृति के नाम पर आज देश में बहुत से कार्य प्रारंभ हो गए हैं। हर कहीं हम Cultural Progress का नाम सुनते हैं। हमारे कलाकार सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के रूप में विदेश जाते हैं, अन्य देशों से हम संस्कृति का संबंध जोड़ते हैं आदि। कहने का तात्पर्य यह कि हम नाच-गान को ही संस्कृति मान बैठते हैं।

भारत के विचारकों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गाना, नाचना, नाटक खेलना मात्र ही संस्कृति है। यदि यही संस्कृति की परिभाषा है तो इसका प्रचार हमारे पूर्वज ऋषियों, विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों द्वारा न होकर फिल्म अभिनेता तथा अभिनेत्रियों द्वारा ही होगा।

संस्कृति शब्द को आज गलत अर्थ ही दिया गया है। यह अज्ञानवश हो सकता है और जानबूझकर भी। जानबूझकर इसलिए कि अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वे संस्कृति शब्द का उपयोग उन लोगों में गलत धारणा पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जैसे डालडा को घी की संज्ञा देने से यह बात स्पष्ट है। घी शब्द के बारे में लोगों की धारणा अच्छी है। इसलिए डालडा के साथ साफ किया हुआ तेल-ऐसा न जोड़कर घी शब्द जोड़ दिया गया है। कुछ समय उपरांत लोग इस डालडा को ही वास्तविक घी समझकर इसका उपयोग करने में लज्जा महसूस

नहीं करेंगे। ठीक यही बात संस्कृति के संबंध में है। संस्कृति के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उन्हें गलत रास्ते पर डालने के लिए इस नवीन संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीयता के संबंध में भी यही बात हुई । हमें Indian Nationalism की भ्रांत धारणा दी गई और कहा गया कि मुसलमान, ईसाई सभी यहां के राष्ट्रीय हैं। सिक्खों को यह गलत धारणा दी गई कि वे हिंदू नहीं हैं आदि।

आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में इसी कारण लोगों की कल्पना नाचने-गाने की ही हो गई है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं कि हमारा कार्य सांस्कृतिक है, परंतु हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां तो नाच-गाना होता नहीं। फिर मैंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि जिस प्रकार नाचने-गाने में वे स्वर-ताल का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार संघ के कार्यक्रमों में एक कहने पर बायां पैर और दो कहने पर दायां पैर निकलता है और एक ताल के अनुसार कार्य होता है, इसलिए यह भी सांस्कृतिक हुआ।

संस्कृति के पीछे क्या भाव है, यह समझना कुछ कठिन है। संस्कृति शब्द का प्रयोग वेदों को छोड़कर अन्य प्राचीन वाङ्मय में नहीं हुआ। संस्कृति को धर्म के अंतर्गत ही मान लिया गया था, परंतु आज संस्कृति शब्द का व्यापक प्रचार होने के कारण लोग इस शब्द को सुनकर चौंकते नहीं। कुछ लोगों ने इसे Culture के अनुवाद के रूप में स्वीकार किया है।

यह भी संभावना हो सकती है कि यह शब्द स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ हो। संस्कृति से मिलता-जुलता संस्कार शब्द हमारा पूर्व परिचित शब्द है। हमारे यहां सोलह संस्कार होते हैं, संस्कारों से मनुष्य बनता है, बिना संस्कार के वह पशु समान है-ऐसा बराबर सुनने में आता है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि जो बाह्य वातावरण है, उसका मनुष्य पर जो परिणाम होता है, उसे हम संस्कार (Impression) कह सकते हैं।

परंतु संस्कार अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। किसी को चोरी की आदत लग जाए तो हम कहेंगे, उस पर बुरे संस्कार पड़े हैं। परंतु जब हम संस्कार कहते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय अच्छे संस्कार से ही होता है। बुरे संस्कारों के लिए हम कुसंस्कार शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे चरित्रवान कहने से हमारा आशय अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति से होता है, जबकि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए हम चरित्रहीन शब्द का प्रयोग करते हैं।

अतः संस्कृति का अर्थ हुआ, अच्छे संस्कारों का परिणाम (प्रभाव)। मलयालम भाषा में हिंदू संस्कृति के लिए हिंदू संस्कार शब्द का प्रयोग होता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किन संस्कारों को हम अच्छा कहेंगे और किनको बुरा। इसकी व्याख्या करना सरल नहीं। पर एक छोटी सी कसौटी तो है। वह यह कि समाज के ध्येय के लिए जो पोषक है, वह अच्छा और जो बाधक है, वह बुरा। जैसे यदि हमारा लक्ष्य दिल्ली जाना है, तो जो रेलगाड़ी या मोटरगाड़ी उधर ले जाने में सहायक हो, वह अच्छी और जो विपरीत दिशा में ले जानेवाली है, वह बुरी।

परंतु दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ध्येय क्या है? इस संबंध में हम इतना जानते हैं कि हमारी जो एकात्मकता है, एकीकरण है, इसकी अनुभूति ही हमारा ध्येय है। जब सब लोग एकता का अनुभव करें, तभी समाज अथवा राष्ट्र बनता है। यदि हम राष्ट्र के नाते जीवित रहना चाहते हैं तो एकात्मकता की अनुभूति जिससे होगी, वही हमारा ध्येय होगा।

यदि पांव में कांटा चुभ जाए और पता न लगे कि कहां चुभा है तो चिंता होने लगती है। शरीर के कण-कण की जब तक ठीक अनुभूति रहती है, तब तक ठीक है, परंतु जब बेहोशी आदि में शरीर का ज्ञान नहीं रहता, क्रियाओं, चेष्टाओं का ज्ञान नहीं रहता तो वह स्थिति चिंताजनक होती है और सारा शरीर गया, ऐसा लगने लगता है। जैसे लकवे में, हाथ होते हुए भी हाथ की क्रिया रुक जाती है, हाथ की अनुभूति नहीं होती। जब तक शरीर में चेतना है, अंगों का संबंध बराबर बना रहता है। तभी तक हममें सामर्थ्य है, जीवन है। इसी प्रकार राष्ट्र रूपी शरीर में चेतना बनाए रखना आवश्यक है। अतः जिन कारणों से राष्ट्र में चेतना का निर्माण होता है, वे अच्छे और दूसरे बुरे।

प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जिससे बनी रहे, वही संस्कृति का आधार माना जाता है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। आत्मा निकल जाने के पश्चात जैसे सब अंग-प्रत्यंग निश्चेष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार की अवस्था संस्कृति का लोप हो जाने से राष्ट्र की होती है। जैसे यूनान और मिस्र का प्राचीन राज्य समाप्त हो गया। इसका यह अर्थ तो नहीं कि वहां की भूमि, नदियां, पर्वत, व्यक्ति आदि नष्ट हो गए। ये वस्तुएं तो ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं, परंतु व्यक्ति को एकसूत्र में बांधने की जो शक्ति संस्कृति में है, वह शक्ति समाप्त हो जाती है।

लकड़ियों को सूत के धागे से बांधा जा सकता है परंतु व्यक्ति-व्यक्ति को बांधने वाला सूत्र संस्कृति ही है। यह सूत्र वर्तमान प्राणियों के अतिरिक्त हमारा संबंध हमारे पूर्वजों अर्थात् राम, कृष्ण, शिवा, प्रताप, गोविंद सिंह आदि से तथा आगे जन्म लेने वालों से भी जोड़ देता है। इसी के बूते पर राष्ट्र टिक सकता है। अतः राष्ट्र रूप में जीवित रहने के लिए यही संस्कृति प्राप्तव्य है। अतः सिद्ध हुआ कि सारे समाज को आपस में जोड़ने वाला नाता संस्कृति है। जिन कार्यक्रमों से यह नाता जुड़ता है, वह संस्कार तथा जिन कार्यों से यह नाता टूटने लगता है, वे कुसंस्कार।

डाकुओं में जो स्वार्थ के कारण एकता है, क्या उसे भी संस्कृति मानें? उत्तर मिलेगा-'नहीं।' कुछ देशों की संस्कृति का आधार यद्यपि यह भी है। जैसे अरब में मुसलमानों का संगठन लूट-खसोट के आधार पर ही किया इसी प्रकार इंग्लैंड भी सामूहिक स्वार्थ के नाम पर ही खड़ा हुआ।

परंतु हमने स्वार्थ के आधार पर एकता खड़ी नहीं की। यही हमारी और दूसरों की संस्कृति में अंतर है। जैसे मां से प्रेम करने के भिन्न-भिन्न आधार हो सकते हैं। इसी प्रकार विवाह के भी भिन्न आधार हो सकते हैं। एक यह कि विवाह दो प्राणियों का एकात्मकता के नाते आगे बढ़ना इसलिए है कि घर की देखभाल के लिए पत्नी मिल जाएगी। इसी प्रकार परिवार में हमारे माता-पिता भी शामिल होंगे। परंतु यूरोप में परिवार में मां-बाप नहीं होते।

जीवन में सभी चीजों की ओर देखने की हमारी दृष्टि कुछ भिन्न है। कुछ राष्ट्रों में ईमानदारी को व्यापार के लिए सर्वोत्तम नीति माना जाता है, परंतु हम इसे व्यापार की नीति के रूप में नहीं अपितु जीवन की नीति के रूप में अपनाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग रुचि होती है। यह रुचि भिन्नता मूलतः सब प्राणियों में विद्यमान है। इसी प्रकार राष्ट्रों में भी रुचि भिन्नता है, अपनी-अपनी विशेषता है। सबके आधार भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसके कारण हमारे देश में भी कुछ चीजें हमें रंजित करती हैं और कुछ नहीं। हमारी विशेष प्रवृत्ति है, जिसके आधार पर हम संगठन करते हैं। वह प्रवृत्ति स्वार्थ की नहीं, निःस्वार्थ भाव की है। ▪

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को सिंहस्थ 2028 के लिए बन रहे 29 किमी लंबे घाटों के संबंध में जानकारी दी।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से सौजन्य मुलाकात की।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

▪ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने चिकित्सा महाविद्यालय बैतूल का शिलान्यास किया।

▪ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने महाकाल एवं हरसिद्धि माता के शिखर दर्शन किए।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल जी ने किसानों को भावांतर योजना राशि का अंतरण किया।

▪ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में दर्शन, पूजन किया।

▪ संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है...

पं. दीनदयाल उपाध्याय